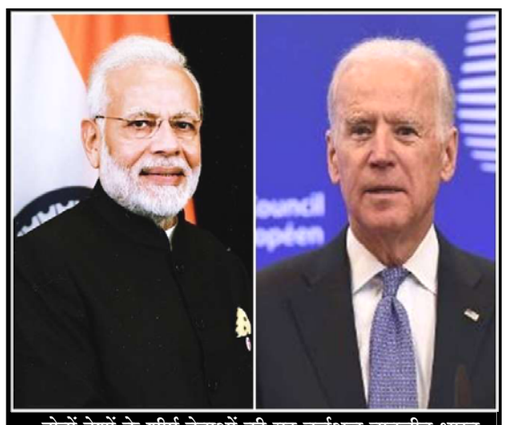

दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की यह वर्चुअल बातचीत भारत-अमेरिका के बीच होने वाली चौथी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता से पहले होगी। टू प्लस टू वार्ता के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंचे हुए हैं।

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:27 अंक: 117 दिनांक: 11-04-2022 सोमवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

रामनवमी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द व मुख्य न्यायाधीष एनवी रमना ने गुजरात के द्वारका मंदिर में परिवार के साथ भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए व पूजा-अर्चना की। राष्ट्रपति ने देश की सुरक्षा समृद्धि के साथ जनता के सुखी होने प्रार्थना की की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति वर्चुअली बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता करेंगे

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति सोमवार को वर्चुअली में द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता करेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका और भारत के बीच अगले हफ्ते 2 प्लस 2 वार्ता भी शुरू होने वाली है, इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल शिरकत करेगा। दोनों देशों के नेताओं के बीच यह कूटनीतिक कवायद ऐसे वक्त हो रही है, जब भारत पर रूस से तेल खरीद आगे न बढ़ाने का दबाव पड़रहा है। एक बयान में कहा गया कि दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और दक्षिण एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मौजूदा गतिविधियों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

पिछले एक-डेढ़ महीनों में भारत में कई देशों के शीर्ष स्तर के नेताओं का आना हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन, उनकी बेटियों और उनके पूरे मुल्क पर आर्थिक प्रतिबंधों के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए थे। विदेश मंत्री एस। जयशंकर से मुलाकात के अलावा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। वहीं अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह भी नई दिल्ली यात्रा पर आए थे और उन्होंने रूस से तेल खरीद को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन विदेश मंत्री एस। जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया भर में तेल के दामों में लगी आग और वैश्विक आपूर्ति शृंखला में रुकावट के बीच भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा।

भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वॉड संगठन भी बनाया है। एलएसी पर जारी विवाद और हिन्द महासागर व प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच इसे महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। हालांकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में तेजी से बदलाव हुए हैं। एक बयान में कहा गया है कि वर्चुअल बैठक के जरिये दोनों देश नियमित और उच्चस्तरीय संपर्क को बढ़ाएंगे और द्विपक्षीय गहन वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे।

फिल्म 'आरआरआर' ने 16वें दिन ही बॉक्स आफिस में धमाल मचाया, कमाई 1000 करोड़ के पार

-ऐसा करने वाली देश की तीसरी फिल्म बनी

मुंबई (ईएमएस)। दक्षिण भारत के फिलमकार एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' ने बॉक्स आफिस पर कमाल करते हुए कमाई में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। एक समय ऐसा हुआ करता था जब किसी भी फिल्म के सक्सेसफुल होने का मापदंड था उसका 100 करोड़ के क्लब में शामिल होना। हर एक्टर की ये इच्छा होती है कि उसकी फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो। लेकिन देखते ही देखते वक्त कितना बदल गया है। जहां 10 साल पहले 100 करोड़ एक बड़ा आंकड़ा माना जाता था वो अब एक आम बात बनती नजर आ रही है। एस एस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' को ही ले लीजिए। फिल्म ने कुल 1000 करोड़ की कमाई कर ली है। 'आरआरआर' की कमाई के अब नए आंकड़े सामने आए हैं।

अमेरिका से कितनी संख्या में खरीदे जाएं प्रीडेटर ड्रोन, इसका निर्धारण करने के लिए सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय समिति

नई दिल्ली । सरकार रक्षा के क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' **(Make in India)** पर जोर दे रही है। वह देश में ही हथियारों के निर्माण को बढ़ावा देने के साथ ही स्वदेशी रक्षा उपकरणों की खरीद भी कर रही है। इसी नीति पर बढ़ते हुए विदेशों से रक्षा उपकरणों के आयात में लगातार कटौती की जा रही है। समाचार एजेंसी एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक अब रक्षा मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है जो निर्धारित करेगी कि अमेरिका से कितनी संख्या में प्रीडेटर ड्रोन की खरीद की जाए.

दरअसल भारत मिसाइलों और स्ट्राइक क्षमता से लैस उच्च ऊंचाई वाले 30 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद करने की योजना बना रहा था। इन ड्रोन को तीनों सेनाओं में शामिल किया जाना था। इस सौदे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में थी। सूत्रों ने एएनआई को बताया कि प्रीडेटर ड्रोन की संख्या तय करने के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है।

दरअसल सरकार का मानना है कि जब तक देश में इस तरह के उपकरणों का विकास नहीं किया जाता तब तक तीनों सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस ड्रोन (ईंदे दहो) की खरीद की जानी चाहिए। सूत्रों ने कहा कि देश की तीनों सेवाओं के लिए इन ड्रोनों की आवश्यकताएं हैं। इन ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी के साथ दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता है।

अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन की अनुमानित लागत तीन अरब डालर बताई जाती है। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पहली बार है जब अमेरिका किसी गैर नाटो सहयोगी देश को ये ड्रोन बेच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की 2017 में अमेरिकी यात्रा के दौरान इस रक्षा सौदे की घोषणा की गई थी। हाल ही में स्वदेशी हथियार प्रणालियों को तरजीह देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर रक्षा मंत्रालय की ओर से आयात किए जाने वाले कई रक्षा सौदों को या तो रद्द कर दिया गया था या इन पर रोक लगा दी गई थी।

लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर पीटीआइ और पीएमएल-एन कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प

लंदन । अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद इमरान खान के हाथों से सत्ता चली गई है। देश में इमरान खान की सरकार गिर गई है। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के समर्थकों के बीच लंदन में बड़ी झड़प हुई। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के आवास एवेनफील्ड फ्लैट्स के बाहर दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच टकराव में विरोधी नेतृत्व के खिलाफ गालियां और नारेबाजी की गई।

पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार की तितर-बितर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) की सरकार गिरने से और इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद लंदन में पीटीआइ के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने रविवार को नवाज शरीफ के आवास पर धरना दिया। प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तान का झंडा थामे पीटीआइ कार्यकर्ताओं ने पीएम को हटाने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बीच, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के समर्थक भी पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एवेनफील्ड फ्लैट्स पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीटीआइ कार्यकर्ताओं के साथ झड़प शुरू कर दी। दोनों समूहों के बीच लंबे वक्त तक जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जारी रहा।

आपको बता दें कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने शीर्ष सीट के लिए नामांकन पत्र जमा किया था, जिसके लिए उनके नामांकन पत्रों को मंजूरी मिल गई है। शहबाज शरीफ के पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बनने की सबसे अधिक संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, पीएमएल-एन ने चुनाव के लिए एनए सचिवालय से एक से ज्यादा नामांकन पत्र जमा किए हैं। ये नामांकन पत्र सोमवार दोपहर 3 बजे जांच के दायरे में आएंगे और जांच के बाद उम्मीदवारों की एक सूची प्रदर्शित की जाएगी।

मायावती का राहुल गांधी पर पलटवार अपने गिरेबान में झांकने की दी नसीहत

नई दिल्ली (ईएमएस)। बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। मायावती ने कहा कि राहुल गांधी ने यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा कि वह अपने बिखरे घर को तो संभाल नहीं पा रहे है। हम पर कटाक्ष कर रहे हैं। रविववार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से घिनौने हाथकंडे अपना रही है। मायावती ने राहुल गांधी को नसीहतें देते हुए कहा कि उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। उन्हें बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मायावती ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक देश पर राज किया पर दलित और शोषित के लिए कुछ नहीं किया। राजीव गांधी ने भी बीएसपी को बदनाम करने की कोशिश की थी। कांशीराम को सीआईए का एजेंट बताया था। मायावती ने कहा कि अब उन्हीं की राह पर चलकर उनके बेटे भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं।

मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार उनकी पार्टी को बदनाम करती रहती है। मायावती ने कहा कि राहुल गांधी अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी की कार्यशैली पर जबरदस्ती उंगली उठा रहे हैं। इससे बीएसपी के प्रति इनकी नफरत और बौखलाहट साफ नजर आती है। मायावती ने कहा, 'इससे पहले इनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी ने भी बीएसपी को बदनाम और कमजोर करने के लिए मान्यवर कांशीराम को सीआईए का एजेंट करार दिया था। अब उनका बेटा (राहुल गांधी) उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए बीएसपी पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगाते रहते हैं।' मायावती ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक देश पर राज किया पर दलित और शोषित के लिए कुछ नहीं किया। मायावती ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दलितों के आर्थिक विकास का पैसा दूसरे मदों में खर्च कर दिया। कांग्रेस ने उनके साथ कुछ नहीं किया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बसपा प्रमुख मायावती पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती ने चुनाव ही नहीं लड़ा। राहुल ने कहा,

मायावती ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दलितों के आर्थिक विकास का पैसा दूसरे मदों में खर्च कर दिया। कांग्रेस ने उनके साथ कुछ नहीं किया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को बसपा प्रमुख मायावती पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती ने चुनाव ही नहीं लड़ा। राहुल ने कहा, ठहमने मायावती को संदेश दिया कि गठबंधन कीजिए और मुख्यमंत्री बनिए। उन्होंने बात तक नहीं की। जिन लोगों ने अपना खून, पसीना देकर उत्तर प्रदेश में दलितों की आवाज को जगाया। आज मायावती कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए नहीं लड़ूंगी।

पहले कांग्रेस नेतृत्व की नाफरमानी, फिर सीएम विजयन की तारीफ, थॉमस के खिलाफ उठी कार्रवाई की मांग

तिरुवनंतपुरम (ईएमएस)। कांग्रेस के खिलाफ जाकर वाम दल के कार्यक्रम में शामिल होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधारकरण ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की तारीफ करने के चलते आलाकमान से थॉमस के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। कांग्रेस ने थॉमस के अलावा थरूर के भी कार्यक्रम में शामिल होने पर रोक लगाई थी। सुधाकरण ने थॉमस पर सीएम के साथ सौदेबाजी के आरोप लगाए हैं।

उन्होंने कहा थॉमस अब कुछ भी कह सकते हैं। वह पार्टी लाइन से दूर जा रहे हैं। कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पार्टी आलाकमान को पत्र भेजा है। चूंकि वह एआईसीसी सदस्य हैं, पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने थॉमस के बयानों पर नाराजगी जाहिर की है। सुधाकरण ने कहा जब वह केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष थे, तो उन्हें विजयन में महानता क्यों नजर नहीं आई। लोकसभा, विधानसभा और केंद्रीय मंत्री होते हुए भी उन्हें विजयन में महानता क्यों नहीं दिखी। उन्हें जरूर कोई सौदा किया होगा, जो उन्हें अब विजयन महान नजर आ रहे हैं।

थामस शनिवार को कन्नूर में आयोजित सीपीआई(एम) के सेमिनार में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरा करने पर सीएम की तारीफ की। सेमिनार में बात करते हुए उन्होंने विजयन की सराहना की और कहा कि वे देश के अच्छे मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर पिनराई विजयन पर मुझे गर्व है। उनकी इच्छाशक्ति के चलते ही केरल में गेल पाइपलाइन का काम पूरा हुआ।

कांग्रेस ने शुरुआत में थॉमस सेमिनार में शामिल होने से मना किया था, लेकिन उन्होंने पार्टी के आदेश की अवहेलना की और कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा मेरा मानना है कि मेरे सहकर्मी इस बात को समझेंगे कि इस कार्यक्रम में मेरा शामिल होना कांग्रेस को मजबूती देगा। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि अगर वे राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए।

बिटकॉइन घोटाले की जांच के लिए एफबीआई ने भारत नहीं भेजी कोई टीम : सीबीआई

नई दिल्ली (ईएमएस)। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) ने बिटकॉइन से जुड़े मामले की जांच के लिए कोई टीम भारत नहीं भेजी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सीबीआई के सीनियर अधिकारी ने बताया कि भारत में इस मामले की जांच करने के लिए एफबीआई ने सीबीआई से ऐसी कोई अपील नहीं की है। ऐसे में भारत में सक्षम प्राधिकारी की ओर से जांच के लिए किसी प्रकार की इजाजत देने का प्रश्न ही नहीं उठता। भारत में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में सीबीआई एफबीआई सहित अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निकटता से समन्वय करती है।

कांग्रेस पार्टी ने पूछा था कि भारत में कथित बिटकॉइन घोटाले की जांच करने के लिए क्या अमेरिका की एफबीआई एजेंसी आई है। कांग्रेस ने पिछले साल कर्नाटक की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने इस घोटाले को छुपाने का प्रयास किया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कथित बिटकॉइन घोटाले की परतें अंततः खुल रही हैं। सुरजेवाला ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को जवाब देना चाहिए कि क्या भारत के सबसे बड़े बिटकॉईनें घोटाले को कर्नाटक भाजपा द्वारा छुपाए जाने की पड़ताल के लिए अमेरिका की एफबीआई आई है? अगर ऐसा है तो इसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।

शिवपाल यादव का मुलायम से भी टूटा दिल पहली बार बड़े भाई के लिए कही ऐसी बात

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (प्रसपा) के प्रमुख शिवपाल यादव अपने भतीजे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज हैं। इसमें तो अब कोई संशय नहीं है। वह जल्द ही सपा से नाता तोड़ने वाले हैं, यह भी साफ हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि पहली बार शिवपाल सिंह यादव ने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से नाराजगी जाहिर की है। इस बीच सपा के निशान पर विधायक बने शिवपाल यादव ने एक बार फिर कहा कि उचित समय आने वाला है और वह जल्द अपने अगले कदम का खुलासा करेंगे। दरअसल, शनिवार को विधानपरिषद चुनाव में वोटिंग के लिए मुलायम कुनबे के अधिकतर सदस्य इटावा में थे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के अलावा सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव और प्रसपा अध्यक्ष और जसवंतनगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने मतदान किया। इस दौरान शिवपाल और रामगोपाल के अलग-अलग बयान सामने आए। जिसने शिवपाल के भाजपा प्रेम के संकेत दिए। हालांकि शिवपाल ने कहा, उनके फैसले का सही समय जल्द आने वाला है। इटावा में वोटिंग के बाद कुछ पत्रकारों ने जब शिवपाल यादव से सवाल किया कि मुलायम सिंह यादव भी आए हुए हैं, क्या आप उनसे मिलेंगे? शिवपाल ने सबको चौंकाते हुए तपाक से कहा, ''आप जाकर मिल लो।''

अमेठी से कांग्रेस के तीन उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराकर प्रियंका गांधी ने इतिहास रच दिया : स्मृति ईरानी

रायबरेली (ईएमएस)। पिछले महीने संपन्न विधानसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस की करारी पराजय पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने कि एक तरह से उन्होंने इतिहास रच दिया जब हाल के विधानसभा चुनाव में अमेठी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के तीन उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कांग्रेस पार्टी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराकर यह सीट जीतने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को प्रियंका का बिना नाम लिए कहा, '2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अमेठी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के तीन उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराकर इतिहास रच दिया, इसके लिए मेरी बधाई।'

उत्तर प्रदेश स्थानीय प्राधिकारण निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले विधान परिषद चुनाव में शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र में वोट डालने पहुंची ईरानी ने संवाददाताओं से कहा, 'आप देखिए, 2019 के चुनावों में कांग्रेस को लगभग 4 लाख वोट मिले, लेकिन 2022 में यह एक लाख के करीब आ गया।' इससे पहले जिले के छतोह विकास खंड के परैया नमकसार पहुंचकर ईरानी ने अष्टमी पर कन्या पूजन में हिस्सा लिया और बाद में किठावा गांव में लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं जानीं। उन्होंने कहा कि वह आठ साल पहले अष्टमी के दिन पहली बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में यहां आई थीं और आज उन्हें भाजपा प्रत्याशी (विधान परिषद में) के लिए एक बार फिर आने का मौका मिला है।

राजनीतिक दलों में कांग्रेस ने सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में शासन किया है, लेकिन वह तीन दशकों से सत्ता से बाहर है। हाल में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान का नेतृत्व प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से भी खराब रहा और पार्टी राज्य की 403 सीटों में सिर्फ दो सीटें रामपुर खास (प्रतापगढ़) और फरेंदा (महराजगंज) ही जीत सकीं। इसके पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सात सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस का गढ़ माने वाले अमेठी और रायबरेली में भी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा जहां कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। उसके उम्मीदवारों को ज्यादातर सीटों पर तीसरा या चौथा स्थान मिला।

चेन्नई समुद्री तट पर ईरानियों धर-पकड़, एनआईए, एनसीबी ने शुरू की नशीली दवाओं की तस्करी की जांच

चेन्नई (ईएमएस)। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के समुद्री तट से 11 ईरानियों को पकड़े जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने नशीली दवाओं की तस्करी की संभावनाओं के मद्देनजर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में गिरफ्तारियां शनिवार को की गईं थी। एनसीबी के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा प्वाइंट के पास एक नाव को रोकने के बाद भारतीय तटरक्षक ने 11 ईरानियों को हिरासत में लिया है, और नाव को कासिमेदु मछली पकड़ने के बंदरगाह तक ले जाया गया। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें नाव से कुछ भी नहीं मिला। आशंका है कि ईरानी तस्करों ने तटरक्षक इंटरसेप्टर नाव को देखने के बाद ड्रग्स को समुद्र में फेंक दिया होगा।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ड्रग्स के स्रोत और भारत में प्रवेश बिंदु और क्या कोई संगठन ड्रग्स की तस्करी में शामिल था, इस पर भी जांच शुरू कर दी है। ध्यान देने योग्य बात है कि अगस्त 2021 में, श्रीलंकाई तमिलों के एक समूह को भारतीय तट पर ड्रग्स की तस्करी करते हुए पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्हें तटरक्षक बल ने रोक लिया और बाद में एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली। जांच करने पर, यह पाया गया कि तस्करी की गई सामग्री का इस्तेमाल लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम की गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया गया था, जो कि निष्क्रिय है। कुछ तमिल राजनीतिक आंदोलन लिट्टे के समर्थन में थे और एनआईए ने तब श्रीलंकाई तमिलों की गिरफ्तारी के संबंध में कई लोगों से पूछताछ की थी। इसी तरह, प्रीमियम जांच एजेंसी जांच कर रही है कि क्या प्रतिबंधित दवाएं किसी नापाक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए थीं। एनआईए तस्करों की पहचान की भी जांच कर रही है क्योंकि एनसीबी तस्करों के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करने की स्थिति में नहीं है। तटरक्षक बल द्वारा गहरे समुद्र में ईरानी नागरिकों को पकड़े जाने के बाद राज्य में किसी भी तस्करी को रोकने के लिए तटरक्षक बल के साथ तमिलनाडु तटीय पुलिस और समुद्री पुलिस भी हाई अलर्ट पर है।

दुनिया के शार्ष स्कूल भारत में खोलने वाले हैं अपनी शाखाएं

-मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु बने पहली पसंद

नई दिल्ली (ईएमएस)। वैश्विक स्तर पर शीर्ष शैक्षणिक संस्थान का तमगा हासिल करने वाले मशहूर स्कूल अब भारत में अपनी शाखाओं को खोलने की कवायद में जुटे हैं। ये स्कूल देश में अब विदेशी स्कूलों के लोकल कैंपस खोलना चाहते हैं। इंग्लैंड का मशहूर मिलफील्ड स्कूल भारत आने को तैयार है। मिलफील्ड स्कूल की स्थापना गुजरात में हुई थी। धांगधरा के महाराजा के बेटों ने इस स्कूल को शुरू किया था। बाद में यह स्कूल यहां से इंग्लैंड में खुल गया। अब यह स्कूल फिर से घर वापसी करने की तैयारी में है। मिलफील्ड स्कूल की नजर दिल्ली और मुंबई पर भी है। ये दोनों शहर इसकी पसंदीदा जगहों में शामिल हैं। मिलफील्ड स्कूल भारत में आने की तैयारी में लगा अकेला नहीं है। यूके हैरो स्कूल ने एमिटी एजुकेशन ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है। ये लोग मिलकर बेंगलुरू में सितंबर 2023 में हैरो इंटरनेशनल स्कूल खोलने जा रहा है। यूके का वेलिंगटन कॉलेज इंटरनेशनल भी पुणे में खुलने वाला है। कई शीर्ष इंटरनेशनल स्कूलों ने लोकल पार्टनर्स के साथ करार किया है। ये भारत में अपना दूसरा कैंपस शुरू करने के लिए तैयार हैं। यूएस रटगर्स प्रेप स्कूल, एडोबु वेंचर्स के साथ साझेदारी में, भारत में सितंबर 2023 में लखनऊ, गाजियाबाद, गुरुग्राम और जयपुर में चार अमेरिकी एडुग्लोबल स्कूल खोलने की योजना बना रहा है।

रामनवमी के पर्व पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का जनसैलाब

अयोध्या (ईएमएस)। रामनवमी के पर्व पर राम की नगरी अयोध्या में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। देशभर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। सुबह से ही सरयू में स्नान के साथ पूजन अर्चन का दौर चल रहा है। सरयू में स्नान के बाद श्रद्धालुओं की ओर से नागेश्वर नाथ, राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला, हनुमानगढ़ी और कनक भवन में पूजन अर्चन किया जा रहा है। अयोध्या की सभी सड़कें श्रद्धालुओं से पटी हुई हैं। पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। यातायात डायवर्सन लागू कर दिया गया है।

जम्मू और कश्मीर एसआईए अलर्ट दिल्ली, हरियाणा समेत कई जगह मारे छापे

जम्मू (ईएमएस)। जम्मू और कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले में रविवार को दिल्ली समेत कई स्थानों पर छापामार कार्रवाई की। खबर है कि एसआईए ने राष्ट्रीय राजधानी में जैश-ए-मोहम्मद के ऑन ग्राउंड वर्कर्स की गतिविधियों के खिलाफ सूचना पर ये कार्रवाई की है। शुक्रवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू और कश्मीर में आतंकी साजिश मामले में 25 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। यह मामला अल्पसंख्यको, नागरिकों, प्रवासियों, सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा जवानों की हत्याओं से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, हरियाणा और कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में रेड की। हाल ही में गठित एसआईए की अलग-अलग टीमें दिल्ली की पांच, हरियाणा और फरीदाबाद की एक और कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक स्थान पर आतंकवाद से जुड़े मामलों में तलाशी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, एसआईए ने जिन स्थानों पर रेड की है, वे संदिग्ध आरोपी के हैं, जो आतंकी गतिविधियों और हवाला या आतंकियों को टेरर फंडिंग में शामिल रहा है। पता चला है कि एसआईए ने उन स्थानों पर रेड की है जहां उन्हें जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकी संगठनों के समर्थकों के ओजीडग्ल्यूएस की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली थी। फरवरी 2022 में एसआईए ने दक्षिण और मध्य कश्मीर में जैश के 10 ओजीडग्ल्यूएस को गिरफ्तार किया था। खास बात है कि मॉडयूल के सदस्यों को इस तरह से बांटा गया था कि अगर एक सदस्य की पहचान हो भी जाती है, तो बड़ा नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं होगा। गिरफ्तार हुए अधिकांश सदस्य स्कूल और कॉलेज के छात्रों को नियुक्त कर रहे थे, क्योंकि इनमें से कई खुद भी छात्र ही थे। ये जैश के आतंकियों के करीबी संपर्क में थे और कुछ समय से एजेंसी के रडार पर थे।

कार्टून कोना

अनंतनाग-कुपवाड़ा के बाद श्रीनगर में आतंकवाद पर सेना का प्रहार, 2 दहशतगर्द ढेर

जम्मू (ईएमएस)। श्रीनगर में जवानों और आंतकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि, मुठभेड़ शुरू हो चुकी है और अभी ऑपरेशन जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि मौके पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम तैनात है। वहीं, अनंतनाग जिले के सिरहामा इलाके में शनिवार को हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी कमांडर मारा गया जबकि कुलगाम में दूसरे ऑपरेशन में आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे। आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि रेडवानी बाला कुलगाम निवासी लश्कर कमांडर निसार अहमद डार, सिरहामा में मारा गया है। वह क्षेत्र में कई अपराधों और हत्याओं में शामिल था। 6 मई 2021 से एक्टिव था। इससे पहले पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने सिरहामा में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था और तलाशी के दौरान जैसे ही संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान पर पहुंची छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चला दीं, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि दूसरे ऑपरेशन में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के दमहल हंजीपोरा के चाकी समद गांव में सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम के साथ एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद आतंकवादी भागने में सफल रहे। क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना पर सुरक्षाबलों ने घेरा और तलाशी अभियान (सीएएसओ) शुरू करने के बाद तड़के करीब चार बजे मुठभेड़ शुरू की। प्रारंभिक गोलीबारी के दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी की और घेरा तोड़ने के लिए हथगोले फेंके।

20 लाख राज्य कर्मचारी और पेंशनभोगियों को कैशलेस इलाज का तोहफा

नई दिल्ली (ईएमएस)। यूपी के राज्य कर्मचारी व पेंशनभोगियों को सरकार कैशलेस इलाज का तोहफा देने जा रही है। अप्रैल के आखिर तक कर्मचारियां को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है। हेल्थ कार्ड से सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मरीज इलाज करा सकेंगे। खासबात यह है कि सरकारी मेडिकल संस्थान व अस्पताल में इलाज पर खर्च होने वाली रकम की कोई बाध्यता नहीं होगी जबकि प्राइवेट अस्पताल में पांच लाख रुपये तक इलाज करा सकेंगे। यूपी में करीब 20 लाख राज्य कर्मचारी व पेंशनभोगियों हैं। इनके पारिवार में सदस्यों की संख्या लगभग 88 लाख है। अभी तक राज्य कर्मचारी व उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं है। ऐसे में इलाज के बिलों के रिम्बर्समेंट लिए कर्मियों को विभाग, अस्पताल व सीएमओ दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बिलों में क

जन हितैषी

अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन दिवसीय एमपीसी की बैठक के नतीजों का ऐलान कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष (2022-2023) की पहली बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट को 4 फीसदी और रिवर्स रेपो को 3.35 फीसदी पर जस का तस रखा है। यानी आपकी ईएमआई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह लगातार 11वीं बार है जब केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट स्थिर रखी है। वहीं बैंक ने वित्तीय वर्ष 23 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.8 से घटाकर 7.2 फीसदी कर दिया है। महंगाई दर का अनुमान 4.5 से बढ़ाकर 5.7 फीसदी किया है। इस बार भी केंद्रीय बैंक ने रेपो दर को बिना किसी बदलाव के यथावत रखा है। अर्थव्यवस्था की चिंता के साथ ही आरबीआई बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में भी सक्रिय दिख रहा है। उपभोक्ताओं के हितों की फिक्र भी उसे है। इसलिए ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए समिति बनाने की बात की है। अब ज्यादातर बैंक डिजिटल सेवाएं दे रहे हैं। इस लिहाज से उपभोक्ता संरक्षण का पक्ष महत्त्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि एमपीसी ने इस बार भी कहा कि उदारता भरा रुख अब ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। इसलिए आने वाले वक्त में रिजर्व बैंक से बेहद उदार रुख की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। मतलब साफ है कि नीतिगत दरों में बदलाव पर विचार हो भी सकता है। लगता है कि एमपीसी आने वाले दिनों के जोखिमों को समझ रही है। इसलिए उसने मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ा कर 5.7 फीसद कर दिया, जबकि इस साल फरवरी में यह साढ़े चार फीसद रखा गया था। इतना ही नहीं, हालात को देखते हुए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान भी घटा कर 7.2 फीसद कर दिया है, जो पहले 7.8 फीसद था। महंगाई और जीडीपी के अनुमानों में बदलाव इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। जहां तक महंगाई की बात है, केंद्रीय बैंक यह पहले से ही कह रहा है कि इस साल यानी 2022-23 में भी महंगाई से मुक्ति नहीं मिलने वाली। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए ही मुद्रास्फीति का अनुमान 6.3 फीसद रखा है। बाकी अगली तीन तिमाहियों में भी यह पांच फीसद से ऊपर ही रहने का अनुमान है। ऐसा इसलिए भी है कि रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दामों में उतार-चढ़ाव बड़ी समस्या बन गया है। इसका असर साफ दिख भी रहा है। पेट्रोल-डीजल से लेकर सीएनजी और पीएनजी तक के दाम जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उससे महंगाई भी बेलगाम होती जा रही है। खाने-पीने के सामान और खाद्य तेलों से लेकर दूसरी जिंसों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। यह तब है जब लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही और बेरोजगारी के आंकड़े डराने वाले हैं। औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों में भी कोई दम नहीं दिख रहा। निजी निवेश और खपत में भी कहीं कोई तेजी नहीं है। एमपीसी ने माना भी है कि आर्थिक गतिविधियां शुरू तो हुई हैं, पर अभी कोविड से पहले वाले स्तर तक आने में समय लगेगा। ऐसे में नीतिगत दरों में किसी भी तरह का बदलाव फिलहाल जोखिम भरा ही साबित होता। अर्थव्यवस्था की चिंता के साथ ही आरबीआई बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में भी सक्रिय दिख रहा है। उपभोक्ताओं के हितों की फिक्र भी उसे है। इसलिए ग्राहक सेवाओं में सुधार के लिए समिति बनाने की बात की है। अब ज्यादातर बैंक डिजिटल सेवाएं दे रहे हैं। इस लिहाज से उपभोक्ता संरक्षण का पक्ष महत्त्वपूर्ण हो जाता है। बैंक ग्राहकों को एक और बड़ी सहूलियत देने की बात है और वह यह कि सभी बैंकों के ग्राहकों को एक ही नेटवर्क पर बिना कार्ड एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा देना। हालांकि अभी कुछ ही बैंक ऐसी सुविधा दे रहे हैं। इससे एटीएम कार्ड धोखाधड़ी के मामलों पर भी अंकुश लगेगा। मौद्रिक नीति समिति के फैसले बता रहे हैं कि अर्थजगत के लिए आने वाला समय कठिनाइयों भरा है। सरकार के लिए भी और आमजन के लिए भी। आर्थिक कुप्रबंधन और महंगाई ने श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों की क्या हालत कर दी, यह हम देख ही रहे हैं। हालांकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में बताया जा रहा है। पर महंगाई से निजात का कोई तोड़ किसी को नहीं सूझ रहा। ऐसे में रिजर्व बैंक के लिए मौद्रिक प्रबंधन बड़ी चुनौती है।

सतत विकासः लोकमूल्यों को आत्मसात करने की आवश्यकता

सतत विकास पर केन्द्रित दो दिवसीय संगोष्ठी भोपाल के मिण्टो हाल में संपन्न हुई। इसमे राज्य के 52 जिलों के सामाजिक, स्वयंसेवी और सामुदायिक संगठनो ने मूलतः आजीविका, स्वास्थ्य, सूक्ष्म वित्त और कृषि क्षेत्र के उन्नयन पर विमर्श कर अनुभवों और जरूरतों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। कार्यक्रम में अजीम फाण्डेशन के प्रमुख अजीम जी, पदमश्री महेश शर्मा, अनुराग बेहार, कुलपति के.जी. सुरेश जैसे वक्ताओं ने अपने विचार साझा किये। अजीम प्रेमजी ने स्वयंसेवी संस्थाओं को सरकारी वित्तपोषण से बचने का आहवान किया। वहीं महेश शर्मा ने उद्यमशील लोगो तक पहुंचने में सरकार की विफलता को रेखांकित किया। सहकारिता मंत्री ने लोकेषणा अर्थात महत्वकांक्षी गुण को त्यागने की तो एक अन्य वक्ताओं ने गुड़ न खाने का उदाहरण देते हुए नैतिकता, इण्डिया से भारत के ग्रामीणजन की आजीविका के लिए स्थानीय उद्योग पर बल दिया। समापन सत्र में संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते मध्यप्रदेश की उत्कृष्ट भूमिका से अवगत कराने के बाद भविष्य के रोडमैप पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने वसुधैव कुटुम्बकम सहित एक ग्रामीण क्षेत्र का उदाहरण देते हुए ऊर्जा साक्षरता के प्रति सजगता का आहवान किया। इससे पूर्व दिल्ली में मध्यप्रदेश सुशासन पर आधारित प्रतिवेदन का विमोचन किया गया, जिसके प्रसार के लिए लगभग आधा दर्जन राष्ट्रीय व प्रादेशिक अखबारो के पूर्णपृष्ठ पर विज्ञापन प्रसारित गया था।

किसी कार्यक्रम के पश्चात होने वाली समीक्षा बैठक में प्रायः हुई त्रुटियों से अनुभव लेकर अगले कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाती है, जिसे विचार मंथन कहते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जिन लक्ष्यों को लेकर कार्यक्रम संपन्न हुआ उसमे पूर्णतः समर्पण का अभाव दिखा। शायद वक्ताओं के उद्बोधन से भी संस्थान ने कोई सबक नहीं लिया इसीलिए तो हर्षध्वनि के रूप में विविध दीर्घा से तालियां गूंज रही थीं। कार्यक्रमस्थल में प्रवेश पूर्व जल सहित आर्थिक भार से बचने के लिए संस्थान सहायको के लिए पृथक से मंगाये गये भोजन पैकेट के प्रवेश को लेकर वाद-विवाद के वावजूद सहभोज उन्हें वंचित रखना, ग्रामीण परिवेश से आये प्रतिभागियों से अंग्रेजी में संभाषण से उत्पन्न नीरसता और अरुचि का वातावरण, वातानुकूलित व दिन में भी अनावश्यक चकाचौध वातावरण में प्रतिबंधित डिस्पोजलों के दुरूपयोग से व्यंजनो का लुत्फ उठाते हुए पर्यावरण व ऊर्जा साक्षरता के व्यवहारिकता का माखौल के साथ ही विचार मंथन का हिन्दी सार प्रस्तुतीकरण की विफलता और दिल्ली में विमोचित पुस्तक के लिए प्रादेशिक अखबारो में विज्ञापन पर लाखों रूपये की बर्बादी सुशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सार्थक होंगे यह यक्ष प्रश्न बना रहेगा।

कार्यक्रम में जिस इंडिया से भारत की ओर आने और लोकेषणा अर्थात महत्वकांक्षा को त्यागने पर बल दिया गया वह दूब व हल्दी से देव की आरती थाली सजाने जैसा अभिव्यंजन है अभिधान नहीं। एक भी धूल न सहने वाले आपके पाहन-नयन सतह से जुड़े मिट्टी से विकसित नलिन नयनों को कैसे निरख पायेंगे? अभिधान को प्रकट करने में हम दोष मानते हैं और अभिव्यंजन के लिए सहृदयता की आवश्यकता पड़ती है जो लोकजीवन में व्याप्त है। इसलिए देश का जीवन भी मृदंग की भांति मुखर(आर्थिक समृद्ध के कीर्तिमानों के साथ) होते हुए भी खोखला(अंत्योदय की अधूरी अवधारणा) है।

(लेखक-राकेश कुमार वर्मा / ईएमएस)

अंग्रेजी को अमित शाह की चुनौती

गृहमंत्री अमित शाह ने कल वह बात कह दी, जो भारत के लिए महर्षि दयानंद, महात्मा गांधी और डॉ. राममनोहर लोहिया कहा करते थे। शाह ने संसदीय राजभाषा समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के नागरिकों को परस्पर संवाद के लिए अंग्रेजी की जगह हिंदी का इस्तेमाल करना चाहिए। याने भारत की संपर्क भाषा अंग्रेजी नहीं, हिंदी होनी चाहिए! इसमें उन्होंने गलत क्या कहा? भारत को आजाद हुए 75 साल हो रहे हैं और हम अभी भी अंग्रेजी की गुलामी कर रहे हैं। अंग्रेजी न केवल भारत के मुट्ठीभर लोगों की भाषा है बल्कि यह भारत की असली राजभाषा है। राजभाषा के नाम पर हिंदी तो शुद्ध ढोंग है। अब भी सरकार के सारे महत्वपूर्ण काम अंग्रेजी में होते हैं। भारत का कानून, न्याय, राजकाज, उच्च शिक्षण, शोध, च्%च्दृलृछ्छ– सब कुछ अंग्रेजी में होता है। हमारे अनपढ़ और अधपढ़ नेताओं में हिम्मत ही नहीं कि वे अंग्रेजी की इस गुलामी को चुनौती दें। अंग्रेजी महारानी बनी हुई है और समस्त भारतीय भाषाएं उसकी नौकरानियां बन चुकी हैं। इस स्थिति को बदलने का काम हिंदी लाओ नहीं, अंग्रेजी हटाओ के नारे से होगा। अमित शाह को मैं बधाई दूंगा कि वे भारत के ऐसे पहले गृहमंत्री हैं, जिन्होंने दो-टूक शब्दों में अंग्रेजी हटाओ का नारा दिया है। अंग्रेजी हटाओ का मतलब यह नहीं है कि अंग्रेजी मिटाओ। जो स्वेच्छा से अंग्रेजी तो क्या, कोई भी विदेशी भाषा पढ़ना चाहे, उसमें काम करना चाहे, जरुर करे लेकिन बस, वह थोपी नहीं जाए। अगर अंग्रेजी थोपी नहीं जाए तो हिंदी थोपना भी उतना ही गलत है। हिंदी के प्रचलन से यदि किसी अहिंदीभाषी को कोई नुकसान होता हो तो मैं उसका सख्त विरोध करुंगा। अमित शाह अपने भाषण में जरा यह कह देते कि अंग्रेजी हटाओ और उसकी जगह भारतीय भाषाएं लाओ तो इस वक्त जो तूफान उठ खड़ा हुआ है, वह नहीं होता। गुजरातीभाषी अमित शाह के भोलेपन पर कई दक्षिण भारतीय नेताओं को भड़कने का मौका मिल गया। यदि अमित शाह यह कह दें और जो कहें, उसे करें भी कि हिंदीभाषी लोग अन्य भारतीय भाषाएं निष्ठापूर्वक सीखें तो इन अंग्रेजीप्रेमियों की बोलती बंद हो जाएगी। जितने अंग्रेजीप्रेमी दक्षिण भारत में हैं, उससे ज्यादा उत्तर भारत में हैं। ये कितने हैं ? इनकी संख्या मुश्किल से 8-10 करोड़ होगी। ये लोग कौन हैं? इनमें से ज्यादातर शहरी, उच्च जातीय और मालदार लोग हैं। यही देश का शासक-वर्ग है। यदि अंग्रेजी हट गई तो देश के गरीब, ग्रामीण, पिछड़े, वंचित लोगों के लिए उच्च शिक्षा, उच्च सेवा, उच्च पदों, उच्च आय और उच्च जीवन के मार्ग खुल जाएंगे। अंग्रेजों के ज़माने से बंद इन दरवाजों के खुलते ही देश में समतामूलक क्रांति का सूत्रपात अपने आप हो जाएगा। भारत में सच्चा लोकतंत्र कायम हो जाएगा। लोकभाषाओं को आपस में कौनसी भाषा जोड़ सकती है? वह हिंदी ही हो सकती है? जो संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी का विरोध करते हैं, वे अपनी भाषा बोलनेवाले के पक्के दुश्मन हैं। गैर-हिंदी प्रदेशों की आम जनता का अंग्रेजी से कुछ लेना-देना नहीं है। यह सिर्फ उनके तथाकथित भद्रलोक का रोना है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के करोड़ों ग्रामीण, किसान, मजदूर, महिलाएं, हिंदू-मुस्लिम तीर्थयात्री और पर्यटक जब एक-दूसरे के प्रदेशों में जाते हैं तो क्या वे अंग्रेजी में संवाद करते हैं? वे हिंदी में करते हैं। अंग्रेजी दादागीरी की भाषा है और हिंदी प्रेम की भाषा है। वह सहज है।

(डॉ. वैदिक अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के कर्णधार रहे हैं।) (लेखक- डॉ. वेदप्रताप वैदिक/ईएमएस)

जलवायु संकट का कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं, मगर उम्मीद अभी बाक़ी है

आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट इस बात की गवाही देती है कि दुनिया प्रदूषण उत्सर्जन न्यूनीकरण के लक्ष्यों को हासिल कर पाने की राह पर नहीं है। इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिये जरूरी है कि प्रयासों को दोगुना किया जाए और नुकसान को जहां तक हो सके, कम किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र के अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) की नयी रिपोर्ट पेश करते वक्त एक चेतावनी भरा वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि ''दुनिया नींद में एक जलवायु प्रेरित तबाही की तरफ बढ़ती जा रही है।'' समाधान पर आधारित इस रिपोर्ट में जलवायु संकट के विज्ञान और उसके प्रभावों के बारे में पूर्व में जारी रिपोर्टों से भी तथ्य लिये गये हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की जाती है, मगर 195 सरकारें उनकी समीक्षा के साथ-साथ अनुमोदन भी करती हैं। यह एक श्रमसाध्य और परत-दर-परत प्रक्रिया है जो इसी हफ्ते सम्पन्न हुई है।

तो जलवायु संकट आखिर है कितना बुरा? वर्ष 2010-2019 इतिहास का ऐसा दशक साबित हुआ जब दुनिया में प्रदूषणकारी तत्वों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन हुआ। हालांकि इसकी रफ्तार कम है और विभिन्न क्षेत्रों और सेक्टरों में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में गहन और फौरी गिरावट नहीं लायी गयी तो वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य पहुंच से बाहर हो जाएगा।

क्या यह कयामत के दिन का पैगाम है? नहीं, मगर यह हमारे आंखें खोलने वाला है कि आखिर कैसे हमें सामने खडी चुनौतियों के बारे में सोचने के अपने नजरिये में बारीकी से बदलाव करना चाहिये। डेढ़ या 2 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान देने के बजाय यह ज्यादा उपयोगी होगा कि हम ऐसे रास्ते तलाशें जिनसे वार्मिंग को जहां तक सम्भव हो सके जल्द से जल्द कम किया जा सके। उदाहरण के तौर पर 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.6 डिग्री से बेहतर है। उसी तरह 1.6 डिग्री, 1.7 डिग्री सेल्सियस से बेहतर है। इसी तरह यह सिलसिला आगे चलाया जा सकता है। ऐसा करने के लिये वर्ष 2030 से पहले वैश्विक स्तर पर 27-43 डिग्री सेल्सियस के बीच गहरी गिरावट लानी पड़ेगी ताकि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि को 1.5-2 सेल्सियस तक सीमित किया जा सके। इसके अलावा भविष्य के ऐसे नेट जीरो लक्ष्य भी तय किये जाने चाहिये, जो सुर्खियां बनें।

लिहाजा, रिपोर्ट के ज्यादातर हिस्से में प्रगति के संकेतों और भविष्य के समाधानों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसमें ऊर्जा, जमीन, निर्माण, परिवहन तथा मांग सम्बन्धी नीतिगत विकल्पों की एक व्यापक श्रंखला दी गयी है, ताकि उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक 20 डॉलर प्रति टन कार्बन डाई ऑक्साइड इक्वेलेंट (टीसीओ2ई) तक कम किया जा सके। या फिर शुद्ध लाभ के साथ भी और 100 डॉलर प्रति टीसीओ2ई के तहत 25 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती की जा सके। साथ ही साथ प्रमुख प्रौद्योगिकियों, जैसे कि सौर ऊर्जा और बैटरियों की कीमतों में 2010 से अब तक 85 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। वहीं, वायु बिजली की लागत भी 55 प्रतिशत तक कम हुई है।

इन मौकों का फायदा उठाया जा रहा है और इसके सुबूत भी हैं। दुनिया भर में अनेक अन्य नीतियां भी लागू की जा रही है। इस बात के सुबूतों की संख्या लगातार बढ़ रही है कि इन नीतियों से ऊर्जा दक्षता बढ़ रही है, वनों का कटान कम हो रहा है और अक्षय ऊर्जा क्षमता को ऊर्जा के मुख्य स्त्रोत के रूप में इस्तेमाल बढ़ रहा है। वर्ष 2020 तक दुनिया के 56 देशों में उत्सर्जन का 53 प्रतिशत हिस्सा जलवायु को समर्पित कानूनों के दायरे में लाया जाता था। वहीं ऊर्जा दक्षता तथा भू-उपयोग जैसे 690 कानून प्रदूषण उत्सर्जन पर अप्रत्यक्ष रूप से अंकुश लगाते थे। कम से कम एक अध्ययन से यह पता चलता है कि इन सभी कानूनों और नीतियों का प्रभाव ऐसा है कि उनसे एक साल में उत्सर्जन में करीब 10 प्रतिशत की कमी लायी जा सकती है।

रिपोर्ट और आगे बढ़कर यह आग्रह करती है कि सभी देशों को, चाहे वे अमीर हों या गरीब, अपने विकास के रास्तों को सततता की तरफ मोड़ने के बारे में सोचना चाहिये। इसका यह मतलब है कि व्यापक आर्थिक और सामाजिक स्थानांतरण जलवायु न्यूनीकरण के परिणाम हासिल करने के लिये उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने कि निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियां।

इस हिसाब से देखें तो नगरों की भविष्य की योजनाओं को जलवायु सम्बन्धी निर्णयों के चश्मे से भी देखा जा रहा है क्योंकि ऐसे फैसलों के जरिये नगरों के अंदरूनी हिस्सों को कारोबार और जीवन दोनों के ही लिये अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकता है। इससे परिवहन लागतों के साथ-साथ प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में भी कमी लायी जाती है। रोजगार सृजन की रणनीतियों में भविष्य के उद्योगों को भी शामिल किया जा सकता है, जिनमें से कई में निम्न-कार्बन विकल्प शामिल हैं। तेजी से विकसित हो रहे देशों के लिये भविष्य की जलवायु से सम्बन्धित सरोकारों को भी खासतौर पर नीतियों का अभिन्न अंग बनाना महत्वपूर्ण है, ताकि आगे चलकर उच्च कार्बन वाले उपायों पर अटकने वाली स्थितियों को टाला जा सके।

तस्वीर का दूसरा पहलू भी सच है। उत्सर्जन में ज्यादा कटौती नहीं हुई तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विकास की दिशा में हुई प्रगति का मूल्य कम कर देंगे। दूसरे शब्दों में मुख्यधारा के विकास निर्णय दरअसल जलवायु सम्बन्धी फैसले भी होते हैं। इस तरह से जलवायु संकट और विकास के बीच संबंधों के बारे में सोचने से कई और निम्न कार्बन मार्ग खुलते हैं जो सामाजिक रूप से सकारात्मक परिणाम भी देते हैं।

यहां कहने का यह मतलब कतई नहीं है कि इस दृष्टिकोण को लागू करना आसान या सीधी सी बात है। दरअसल, इनमें से हरेक को अलग-अलग लेने की तुलना में इन परस्पर जुड़ी समस्याओं पर विचार करना यकीनन ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। मगर यह भी कहना ठीक है कि जलवायु संकट की प्रकृति को देखते हुए अब यह भी जरूरी हो गया है।

रिपोर्ट में कम से कम दो अतिरिक्त कारकों को रेखांकित किया गया है जिन्हें इस रास्ते को अपनाने से पहले हल करने की जरूरत है। पहला, जहां विकास निर्णयों में जलवायु संकट को आंतरिक करने से भविष्य में बड़े लाभ मिल सकते हैं, इसके लिए पर्याप्त अग्रिम निवेश लागत की भी आवश्यकता हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय प्रवाह वर्तमान में 2030 तक अनुमानित जरूरतों की तुलना में 3-6 गुना कम है। हालांकि यह अनुपात दुनिया के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से विकासशील क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है।

दूसरा, सरकारों को ये जटिल रूपांतरण सम्भालने के लिये अपनी क्षमता का निर्माण करने की जरूरत है। निम्न-कार्बन अवसरों के माध्यम से रणनीतिक रूप से सोचने के लिए, कई क्षेत्रों और पैमानों पर समन्वय स्थापित करने और जोखिम से घिरी आबादी पर विघटनकारी परिवर्तनों के प्रभावों को सीमित करने के लिए जलवायु के लिहाज से तैयार एक राज्य के निर्माण की जरूरत होती है।

आखिरकार, यह रिपोर्ट इस बात को बिल्कुल साफ करती है कि विकास रूपांतरण के रास्ते हर देशों के हिसाब से अलग-अलग होने जा रहे हैं और समस्या का कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं है। हालांकि, यह रिपोर्ट वे सारी चीजें प्रदान करती है जिनका उपयोग देशों में नीति निर्माता संदर्भ-विशिष्ट तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि रूपरेखाएं, संस्थान, नीतियां और प्रौद्योगिकियां।

दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर अंतरराष्ट्रीय संवाद प्रक्रिया के तहत तय किये गये उत्सर्जन न्यूनीकरण के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ रही है। मगर उसे न्यूनीकरण के प्रयासों को आईपीसीसी के आकलन के अनुरूप फिर से दोगुना करना चाहिये ताकि नुकसान को जहां तक हो सके, कम किया जा सके। (लेखक- नवरोज के दुबाष/ ईएमएस)

आज का इतिहास 11 अप्रैल

1564 इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध समाप्त हुआ.
1689 विलियम और मेरी इंग्लैंड के राजा और रानी बने.
1814 नेपोलियन बोनापार्ट ने गद्दी बिना शर्त छोड़ दी.
1887 कलाकार जामिनी राय का जन्म हुआ .
1899 स्पेन ने फिलीपीस अमेरिका को सौप दिया.
1919 न्यूजीलैंड के लोगों ने जनमत संग्रह मद्ध निषेध का विरोध किया.
1930 ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला आम जनता के लिए खोल दिया गया.
1961 नाइजीरिया ने दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया
1964 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ.
1989 अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर की नाकेबंदी मुस्लिम विद्रोहियों ने कर दी.
1991 सुरक्षा परिषद् ने खाड़ी युद्ध समाप्त होने की विधिवत घोषणा की.
2002 सुप्रीम कोर्ट द्वारा अल्पसंख्यक शब्द पर नये सिरे से विचार करने का निर्णय.

शब्द पहेली - 7252

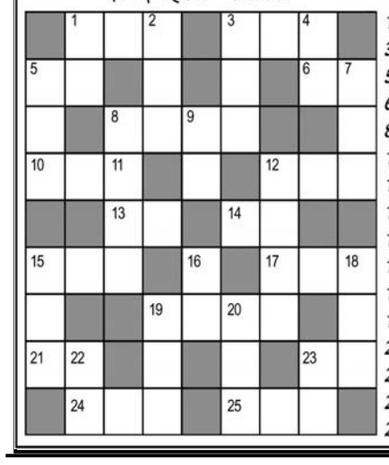

बाएँ से दाएँ

1.सावधान,सचेत-3
3.खूबसूरत-3
5.वचन,प्रतिज्ञा-2
6.हत्या,मर्डर-2
8.तब तक,अवधि में-4
10.चरित्र,लक्षण-3
12.रूस की मुद्रा-3
13.परागकण-2
14.नाखून-2
15.छुटकारा,आजादी-3
17.तट,किनारा-3
19.ईश्वर,भगवान -4
21.अधीन,काबू-2
23.नवीन,नवजात-2
24.लेखनी,पेन-3
25.लाईन,रेखा -3

ऊपर से नीचे

1.हमेशा,सदैव-2
2.विष,जहर-3
3.गर्भ-3
4.नया,नवल-2
5.पुनरागमन-3
7.मस्ती,उछलकूद-3
8.स्वभाव,आदत-4
9.नुकसान,घाटा-2
12.कपोल,गाल-4
15.शान्ति,सन्नाटा-3
16.ताकत,दम,बल-2
18.बोलने का तरीका-3
19.प्रतिज्ञा,वचन-3
20.आज्ञापालन-3
22.वहम,संदेह-2
23.लोहे की तांत-2

शब्द पहेली -7251 का हल

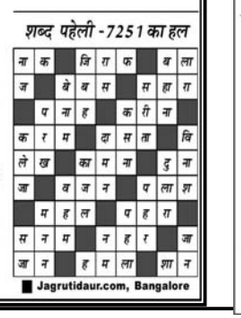

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

11 अप्रैल 2022 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	मीन में	मेष	05.56 बजे से
चंद्र	कर्क में	वृष	07.36 बजे से
मंगल	कुंभ में	मिथुन	09.35 बजे से
बुध	मेष में	कर्क	11.48 बजे से
गुरु	कुंभ में	सिंह	14.04 बजे से
शुक्र	कुंभ में	कन्या	16.16 बजे से
शनि	मकर में	तुला	18.27 बजे से
राहु	वृष में	वृश्चिक	20.41 ब.से
केतु	वृश्चिक में	धनु	22.57 बजे से
राहुकाल 7.30 से 9.00 बजे तक		मकर	01.03 बजे से
		कुंभ	02.49 बजे से
		मीन	04.22 बजे से

सोमवार 2022 वर्ष का 101 वां दिन
दिशाशूल पूर्व **ऋतु** बसंत।
विक्रम संवत् 2079 **शक संवत्** 1944
मास चैत्र **पक्ष** शुक्ल
तिथि दशमी 04.31 बजे प्रातः को समाप्त।
नक्षत्र पुष्य 06.51 बजे को समाप्त।
योग धृति 12.18 बजे को समाप्त।
करण तैतिल 15.59 बजे तदनन्तर गर 04.31 बजे प्रातः को समाप्त।
चन्द्रायु 09.7 घण्टे
रवि क्रान्ति उत्तर 08° 14'
सूर्य उत्तरायन
कलि अहर्गण 1871215
जूलियन दिन 2459680.5
कलियुग संवत् 5123
कल्पारंभ संवत् 1972949123
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885123
वीरनिर्वाण संवत् 2548
हिजरी सन् 1443
महीना रमजान
तारीख 09

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
अमृत	05.53 से	07.22 बजे तक	चर	05.43 से	07.14 बजे तक
काल	07.22 से	08.50 बजे तक	रोग	07.14 से	08.45 बजे तक
शुभ	08.50 से	10.19 बजे तक	काल	08.45 से	10.17 बजे तक
रोग	10.19 से	11.48 बजे तक	लाभ	10.17 से	11.48 बजे तक
उद्वेग	11.48 से	01.17 बजे तक	उद्वेग	11.48 से	01.19 बजे तक
चर	01.17 से	02.45 बजे तक	शुभ	01.19 से	02.51 बजे तक
लाभ	02.45 से	04.14 बजे तक	अमृत	02.51 से	04.2 बजे तक
अमृत	04.14 से	05.43 बजे तक	चर	04.22 से	05.53 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ– शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

भारतीय महिला हॉकी टीम के इंग्लैंड के खिलाफ प्रो लीग मैच रद्द

भुवनेश्वर (ईएमएस)। भारतीय महिला हॉकी टीम के इंग्लैंड के खिलाफ एफआईएच प्रो लीग के दो मैच रद्द कर दिए गए हैं जिन्हें पहले विपक्षी टीम में कोविड-19 संबंधित मामलों के कारण स्थगित कर दिया गया था। इससे सविता की अगुआई वाली टीम तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगी।

भारतीय टीम को इन रद्द हुए मैचों से छह अंक (प्रत्येक मैच से तीन-तीन अंक) मिले हैं। इन दोनों मैचों को पहले यहां कलिंग स्टेडियम में दो और तीन अप्रैल को होना था लेकिन इंग्लैंड में कोविड-19 मामलों और चोटिल खिलाड़ियों की काफी संख्या के कारण स्थगित कर दिया गया था।

विश्व संचालन संस्था एफआईएच ने एक बयान में कहा एफआईएच हॉकी प्रो लीग के भारत और इंग्लैंड महिला टीमों के बीच भारत के भुवनेश्वर में दो और तीन अप्रैल को होने वाले मैचों को दुर्भाग्य से आखिर में रद्द करना पड़ेगा जिन्हें इंग्लैंड की टीम में कोविड-19 के काफी मामलों और चोट के कारण स्थगित किया गया था।

इसमें कहा गया हॉकी इंडिया, इंग्लैंड हॉकी और एफआईएच के सभी प्रयासों के बावजूद भारत में इन मैचों को कराने के लिए कोई तारीख नहीं मिली। परिणामस्वरूप एफआईएच और दोनों देशों के बीच सहमति बनी कि इन दो मैचों के लिये उपलब्ध छह अंक भारत को प्रदान कर दिये जाएंगे। दोनों रद्द मैचों से छह अंक मिलने से भारत ने तालिका में ओलंपिक चैम्पियन नीदरलैंड को पीछे छोड़कर 22 अंक से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। नीदरलैंड 19 अंक से दूसरे और जर्मनी 13 अंक से तीसरे स्थान पर है।

मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स तरसी जीत के लिए

-चार टीमों ने इस हफ्ते नहीं गंवाया एक भी मुकाबला

नई दिल्ली(ईएमएस)। दूसरे सप्ताह में भी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स को जीत नहीं मिल सकी। आरसीबी सहित 4 टीमों ने अपने 100 फीसदी मुकाबले जीते। वहीं दिल्ली कैपिटल्स सहित 4 टीमों को जीत के लिए तरसना पड़ा। 3 से 9 अप्रैल के बीच कुल 8 मुकालबे खेले गए। सभी 10 टीमों को कम से कम एक-एक मैच खेलने का मौका मिला।

पॉइंट टेबल में अभी केकेआर की टीम 6 अंक के साथ टॉप पर चल रही है। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन सीएसके की टीम सबसे निचले 10वें नंबर पर है। केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस दौरान 2 मुकाबले खेले और दोनों में जीत हासिल की। टीम ने एक मैच में सनराइजर्स हैदराबादको 12 रन से जबकि दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से मात दी। इस दौरान आरसीबी ने भी अपने दोनों मैच में जीत हासिल की। टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से जबकि मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। केकेआर और गुजरात ने इस हफ्ते एक-एक ही मैच खेला और जीत हासिल की। केकेआर ने मुंबई को 5 विकेट से जबकि गुजरात ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया।मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स ने इस हफ्ते 2-2 मुकाबला गंवाया। इसके अलावा राजस्थान और दिल्ली को भी जीत नहीं मिली।

मुंबई को आरसीबी और केकेआर से हार मिली। वहीं सीएसके ने पंजाब और हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला गंवाया। राजस्थान रॉयल्स को आरसीबी ने 4 विकेट से जबकि दिल्ली कैपिटल्स को लखनऊ सुपर जायंसट ने 6 विकेट से मात दी। अन्य 2 टीमों के लिए हफ्ता मिला-जुला रहा। पंजाब किंग्स ने 2 मैच खेले। एक में जीत हासिल की, जबकि एक में हार। टीम ने चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ 54 रन से बड़ी जीत हासिल की। लेकिन टीम गुजरात से 6 विकेट से हार गई। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने सीएसके के खिलाफ 8 विकेट से बड़ी जीत हासिल की।

फ्रेंच लीग : एमबापे और नेमार की हैट्रिक, पे

रमीज राजा टी20 आयोजन सहित भारत-पाक सहित चार देशों के टूर्नामेंट के प्रस्ताव को अन्य देशों का मिला समर्थन

लाहौर (ईएमएस)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष रमीज़ राजा आईसीसी के समक्ष ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और भारत के बीच एक वार्षिक चतुष्कोणीय टूर्नामेंट के आयोजन का प्रस्ताव रखने वाले हैं। इस टूर्नामेंट के आयोजन के पीछे रमीज़ की दलील है कि यह सभी सदस्यों के लिए राजस्व के अवसर पैदा करेगा। हालांकि इस विशिष्ट योजना के वास्तविकता बनने की संभावना नहीं है। कम से कम अपने वर्तमान स्थिति में तो नहीं, जिसमें भारत और पाकिस्तान को नियमित रूप से खेलने और आठ पूर्ण सदस्यों को बाहर करने की आवश्यकता होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे इस विचार के अधिक समर्थन के लिए प्रेरित किया गया है कि सदस्य खुद के चतुष्कोणीय टूर्नामेंट का आयोजन कर सकें।

वर्तमान समय में, तीन राष्ट्रीय टीमों से अधिक वाले किसी भी टूर्नामेंट को आईसीसी इवेंट माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि यह आईसीसी द्वारा संचालित किया जाता है और व्यवसायिक रूप से यह एक आईसीसी इवेंट होता है। इससे होने वाली आय भी टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों के बीच विभाजित की जाती है। रमीज राजा की चतुष्कोणीय टूर्नामेंट आयोजित कराने की योजना भी यही बताती है कि आईसीसी द्वारा इवेंट को नियंत्रित किया जाता है। दुबई में शुक्रवार को मुख्य कार्यकारी समिति (सीईसी) की बैठक में विभिन्न बोर्ड के सीईओ ने सदस्यों के अपने स्वयं के चतुष्कोणीय आयोजनों को आयोजित करने में सक्षम होने के विचार की वकालत की।

बैठक में घटनाक्रम से अवगत दो अधिकारियों के अनुसार, कई बोडरं ने इस विचार का समर्थन किया। हालांकि इस विचार से सभी सदस्यों की आम सहमति नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड (ईसीबी), ऑस्ट्रेलिया (सीए), वेस्टइंडीज़ (सीडब्ल्यूआई) और पाकिस्तान (पीसीबी) के क्रिकेट बोडर् इसके पक्ष में थे। एक अधिकारी के मुताबिक ईसीबी के सीईओ टॉम हैरिसन ने बैठक में इस विचार को प्रकट किया था। हालांकि हैरिसन का विचार सीधे तौर पर रमीज़ की योजना से जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन पीसीबी के एक अधिकारी ने इसे अपनी जीत करार दिया क्योंकि यह दर्शाता है कि बोर्ड के अन्य सदस्य भी चतुष्कोणीय टूर्नामेंट की परिकल्पना कर रहे हैं।

हालांकि मुख्य कार्यकारी समिति की बैठक में बीसीसीआई का रुख़ अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ऐसे संकेत मिले हैं कि बीसीसीआई ने भी इस चतुष्कोणीय टूर्नामेंट का सीधे तौर पर विरोध नहीं किया। दिसंबर 2019 में चार देशों की सीरीज़ का सबसे पहले प्रस्ताव देने वाले भी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ही थे। विचार कितना आगे जाता है यह सीईसी के बीच समर्थन के स्तर पर निर्भर करता है। ऐसा माना जाता है कि बोडर् के सामने प्रस्ताव रखने से पहले एक स्पष्ट बहुमत से सहमत होने की आवश्यकता होगी और यदि एक बार बोडर् स्तर पर सहमति हो जाती है, तब इवेंट की मंज़ूरी के संबंध में नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। चतुष्कोणीय आयोजनों का प्रश्न किसी भी हाल में बोडर् की बैठक में ही आता क्योंकि रमीज़ हमेशा वहीं अपना प्रेजेंटेशन देने वाले थे। लेकिन वह प्रस्तुति अब व्यापक चर्चा में बदल सकती है।

कंपनियों के तिमाही परिणाम से तय होगी बाजार की चाल

मुंबई (ईएमएस)। ?विदेशी बाजार के कमजोर रहने के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के महंगाई को नियंत्रित करने और विकास की गति को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रमुख नीतिगत दरों को यथावत रखने के निर्णय से बीते सप्ताह तेजी पर रहे शेयर बाजार की चाल इस सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय कारकों के साथ ही कंपनियों की चौथी तिमाही के परिणाम से तय होगी। बीते सप्ताह बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 170.69 अंक की तेजी लेकर सप्ताहांत पर 59447.18 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 126.85 अंक चढ़कर 17797.30 अंक पर रहा। इस दौरान दिग्गज कंपनियों के मुकाबले छोटी और मझौली कंपनियों में अधिक तेजी रही। बीएसई का मिडकैप और स्मॉलकैप में भी अ?धिक तेजी दर्ज की गई। विश्लेषकों का कहना है ?कि समीक्षाधीन सप्ताह शेयर बाजार के लिए उतार-चढ़ाव वाला रहा लेकिन मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में जबरदस्त बढ़त देखी गई और यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है। इस सप्ताह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दो दिग्गज कंपनियों टीसीएस और इंफोसिस के पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के परिणाम जारी होने वाले हैं, जिसका असर शेयर बाजार पर देखा जा सकेगा। टीसीएस का परिणाम 11 अप्रैल और इंफोसिस का 13 अप्रैल को जारी होगा। बाजार के जानकारों का कहना है ?कि इनके अलावा वैश्विक संकेत, कच्चे तेल की कीमत और विदेशी संस्थागत निवेशकों के रुख का भी शेयर बाजार पर असर रहेगा।

देश में सोने का आयात पिछले वित्त वर्ष में 33.34 प्रतिशत बढ़कर 46.14 अरब डॉलर पर पहुंचा

नई दिल्ली (ईएमएस)। लगातार पीली धातु का बढ़ती मांग के चलते देश में सोने का आयात पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में 33.34 प्रतिशत बढ़कर 46.14 अरब डॉलर पर पहुंच गया जिससे देश के चालू खाते के घाटे (कैड) पर असर पड़ने की आशंका है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का सोने का आयात 34.62 अरब डॉलर रहा था। लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 में सोने का आयात बढ़ने से देश का व्यापार घाटा बढ़कर 192.41 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले 102.62 अरब डॉलर रहा था। चीन के बाद भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में सोने का आयात मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 में रत्न एवं आभूषणों का निर्यात करीब 50 प्रतिशत बढ़कर 39 अरब डॉलर पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में देश का चालू खाते का घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.7 प्रतिशत या 23 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

क्रिप्टोकरेंसी पर कराधान को लेकर एफएक्यू पर काम कर रही है सरकार

- एफएक्यू से वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर जीएसटी लगाने के बारे में चीजें स्पष्ट हो सकेंगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। 10 सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर कराधान को लेकर बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) पर काम कर रही है। एक अधिकारी ने कहा कि एफएक्यू से वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर आयकर और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के बारे में चीजें स्पष्ट हो सकेंगी। एफएक्यू के सेट का मसौदा आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), रिजर्व बैंक और राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। विधि मंत्रालय द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी।अधिकारी ने कहा ?कि क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल डिजिटल संपत्ति पर कर को लेकर बार-बार पूछे जाने वाले सवालों पर काम चल रहा है। हालांकि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सूचना के उद्देश्य से होते हैं और इनकी कोई कानूनी वैधता नहीं होती है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें कोई खामी तो नहीं है, विधि मंत्रालय की राय मांगी जा रही है। अधिकारी ने बताया कि डीईए, राजस्व विभाग और रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि फील्ड कर कार्यालय और क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल मुद्राओं का लेनदेन करने वालों के लिए कराधान के पहलू स्पष्ट हो सकें।वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आयकर लगाने के संबंध में चीजें स्पष्ट की गई हैं। एक अप्रैल से इस तरह के लेनदेन पर उसी तरह से 30 प्रतिशत का आयकर, उपकर और अधिभार लगाया जाएगा जैसा कि कर कानून घुड़दौड़ या अन्य सट्टेबाजी वाले लेनदेन पर लगाता है।

बजट 2022-23 में एक साल में वर्चुअल मुद्राओं से 10,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर एक प्रतिशत की स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और इस तरह के उपहारों को प्राप्त करने वालों पर कराधान का भी प्रस्ताव है। इसके तहत कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपये प्रतिवर्ष होगी। इनमें व्यक्ति, एचयूएफ आदि शामिल हैं जिन्हें अपने खातों का आयकर कानून के तहत ऑडिट कराना होगा। एक प्रतिशत टीडीएस का प्रावधान एक जुलाई, 2022 से लागू होगा, जबकि लाभ पर कर एक अप्रैल से लगाया जाएगा। जीएसटी के दृष्टिकोण से एफएक्यू से यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्रिप्टोकरेंसी वस्तु है या सेवा। अभी क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है और इसे वित्तीय सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सरकार ने पिछले आठ वर्षों में विकास कार्यों पर 100 लाख करोड़ खर्च किए

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने पिछले आठ वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों पर करीब 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की एक रिपोर्ट के मुता?बिक वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने विकास संबंधी कार्यों के लिए 90,89,233 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इससे पहले हाल में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014-2021 के बीच ईंधन कर संग्रह से 26.5 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए थे लेकिन मुफ्त खाद्यान्न, महिलाओं को नकद भत्ते, पीएम-किसान और अन्य नकद हस्तांतरण पर किया गया खर्च '2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आंकड़े कुल किए गए खर्च काफी कम है क्योंकि विकास कार्यों पर व्यय लगभग चार गुना था। उन्होंने खर्च का ब्योरा साझा करते हुए बताया कि 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय किया गया है। भोजन, उर्वरक और ईंधन सब्सिडी के लिए 25 लाख करोड़ रुपए और स्वास्थ्य, शिक्षा, किफायती आवास आदि जैसी सामाजिक सेवाओं पर 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए है। जानकारी के मुता?बिक ईंधन कर से एकत्र किया गया पैसा विकास के अच्छे रूप में उपयोग में किया गया है।

एफपीआई ने इस महिने भारतीय शेयर बाजारों में 7,707 करोड़ निवेश किया

नई दिल्ली (ईएमएस)। छह माह तक लगातार बिकवाली के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अप्रैल में अब तक भारतीय शेयर बाजारों में 7,707 करोड़ रुपए का निवेश किया है। शेयर बाजारों में करेक्शन ने एफपीआई को लिवाली का अच्छा अवसर दिया है, जिससे इस महीने वे शुद्ध लिवाल रहे हैं। बाजार के जानकारों ने कहा ?कि एफपीआई प्रवाह को अभी प्रवृत्ति में बदलाव कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। इस मोर्चे पर चीजें अधिक स्पष्ट हो सकें इसके लिए अगले कुछ सप्ताह या माह का इंतजार करना होगा। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 1-8 अप्रैल के दौरान भारतीय शेयरों में 7,707 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि एफपीआई के प्रवाह से संकेत मिलता है कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के पुनर्मूल्यांकन को पूरा कर लिया है। इसके अलावा शेयर बाजारों में हालिया करेक्शन ने भी उनके लिए निवेश के अवसर खोले हैं। हालांकि पिछले दो कारोबारी सत्रों में एफपीआई ने बिकवाली की है। ऐसे में अभी एफपीआई प्रवाह की दिशा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हैं। इससे पहले अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022 तक छह माह में एफपीआई ने शेयरों से 1.48 लाख करोड़ रुपए निकाले थे। समीक्षाधीन अवधि में एफपीआई ने शेयरों के अलावा बांड या ऋण बाजार में भी 1,403 करोड़ रुपए डाले हैं। इससे पिछले दो माह फरवरी-मार्च के दौरान उन्होंने बांड बाजार से 8,705 करोड़ रुपए निकाले थे।

ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्सपो में जुटेंगे 1,500 प्रतिभागी

नई दिल्ली (ईएमएस)। मुंबई में 12 अप्रैल से पहली बार आयोजित होने वाले 'ग्लोबल स्टेनलेस-स्टील एक्सपो (जीएसएसई) 2022 में दुनिया भर से 1,500 से अधिक प्रतिभागी जुटेंगे। जीएसएसई ने कहा कि इस तीन-दिवसीय आयोजन को इस्पात मंत्रालय और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) के सहयोग से किया जा रहा है। आयोजन के दौरान सरकार के प्रतिनिधियों, उद्योग जगत के नेताओं और संघों की उपस्थिति में अतिरिक्त सचिव स्टील रसिका चौबे द्वारा स्टेनलेस स्टील विजन 2047 का उदघाटन किया जाएगा। यह आयोजन उत्पादकों और उपयोगकर्ता उद्योग समेत हितधारकों को अपने उत्पादों को दर्शाने और बाजारों में उपस्थिति बनाने के साथ-साथ देश और विदेशों में व्यापार के अवसरों का पता लगाने का अवसर देगा।

शिवसेना भवन के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने पर चार एमएनएस कार्यकर्ता गिरफ्तार

सीकर (ईएमएस)। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवसेना भवन के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और चार लोगों को हिरासत में ले लिया। गुड़ी पड़वा के दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का विरोध किए जाने के बाद रविवार के दिन दादर में स्थित शिवसेना भवन के सामने एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर लगाया और एक बार फिर शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) मस्जिद के बाहर लगे लाउडस्पीकर का विरोध पुरजोर तरीके से कर रही है।

रविवार सुबह मुंबई के दादर इलाके में स्थित शिवसेना भवन के सामने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं की ओर से लाउडस्पीकर पर भजन बजाए गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जगह जगह पर लाउडस्पीकर बजाते नज़र आए और इसी सिलसिले में राम नवमी के दिन शिवसेना भवन के बाहर स्पीकर बजाया गया। इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने कहा कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना पिछले 25 सालों से बीएमसी की सत्ता में है जहां आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं..... और इन चुनावों से पहले राज ठाकरे अब हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना को घेरने की कोशिश करते दिख रहे हैं। पहले हफ्ते शिवसेना भवन के पास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के की ओर से पोस्टर लगाकर शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल भी उठाया गया था और कहा था कि यह बाल ठाकरे वाली शिवसेना नहीं है।। तो वहीं शिवसेना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के को ज़्यादा महत्त्व देती नज़र नहीं आ रही है।

शिवसेना नेता और मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा, जो खत्म हुई पार्टी है, वो खुद को जिंदा करना चाहती है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हमारा हिंदुत्व सबको पता है।। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए....जो वचन हमने लोगों कल दिया है, वो हम पूरा करेंगे।

कुर्सी छिनते ही बढ़ी इमरान की मुश्किलें, प्रवक्ता के घर पर पड़ा छापा

इस्लामाबाद (ईएमएस)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रवक्ता डॉ अर्सलान खालिद के घर पर रविवार तड़के छापा मारा गया। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी। पार्टी ने दावा किया कि डॉ खालिद के परिवार के सदस्यों के फोन भी जब्त कर लिए गए और अधिकारी उन्हें आपने साथ ले गए। पीटीआई ने हालांकि छापे मारने वाली एजेंसी का नाम नहीं लिया। पार्टी ने ट्वीट करके कहा बेहद परेशान करने वाली खबर, प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रवक्ता डॉ अर्सलान खालिद के घर पर छापे मारे गए हैं और उन्होंने उनके परिवार के सदस्यों से सभी फोन ले लिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा और न ही किसी संस्थान पर हमला किया।

पीटीआई ने दावा किया कि विपक्ष ने निवर्तमान कैबिनेट मंत्रियों या पार्टी सदस्यों के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं करने का वादा किया था, इसके बावजूद छापे मारे गए। पाकिस्तान में इमरान सरकार गिरने के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए पीएमएलएन के नेता शहबाज शरीफ ने कहा वह अपने बड़े भाई पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके घर के लोगों, यहां तक की महिलाओं ने भी जेले काटी हैं। लेकिन वे किसी के खिलाफ बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। नया पाकिस्तान का उदय हुआ है और यह पाकिस्तान कायदे आजम की सिद्धांतों पर फिर से चलेगा। बिलावल भुट्टो ने भी सदन में भाषण दिया और अपनी मां पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और नाना जुल्फिकार अली भुट्टो के संघर्षों को याद किया।

श्रीलंका में गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ जनाक्रोश तेज

-इस्तीफे की मांग को लेकर 10,000 से अधिक लोगों ने किया रातभर प्रदर्शन

कोलंबो (ईएमएस)। आर्थिक रूप से बेहाल हो चुके श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ जनाक्रोश तेज हो गया है उनके इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के तहत 10,000 से अधिक लोग 'गाले फेस ग्रीन' पार्क में इकट्ठे हुए और उन्होंने रातभर प्रदर्शन किया। श्रीलंका ब्रिटेन से 1948 में आजादी हासिल करने के बाद सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देशवासी कई घंटों की बिजटी कटौती, गैस, खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी के विरोध में कई हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को दिन से ही समाज के सभी तबके के लोगों ने गाले फेस में इकट्ठा होना शुरू कर दिया, इसी स्थान पर सचिवालय है और शाम होते-होते पूरा रास्ता प्रदर्शनकारियों से भर गया और यातायात अवरुद्ध हो गया।

एक प्रदर्शनकारी ने रविवार सुबह छह बजे सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा, 'हम अब भी यहां हैं।' प्रत्यदर्शियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने रात भर प्रदर्शन किया। वे राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग करते हुए 'घर जाओ गोटा' जैसे नारे लगा रहा थे। एक प्रदर्शनकारी ने संवाददाताओं से कहा, 'यह मजाक नहीं है। यह यहां इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास बिजली, ईंधन और दवाइयां नहीं है।' एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, 'उन्हें जाना चाहिए, उनके पास कोई रास्ता नहीं हैं।' गौरतलब है कि संकट के समाधान और आर्थिक कुप्रबंधन के लिए राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों लोग कई हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं।

राष्ट्रपति और उनके बड़े भाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली अपने परिवार के सार्वजनिक आक्रोश का केंद्र बनने के बावजूद सत्ता पर काबिज हैं। सरकार का अनुमान है कि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले दो वर्षों में श्रीलंका की पर्यटन पर निर्भर अर्थव्यवस्था को 14 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। सरकार का आर्थिक सहायता के लिए 11 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ बातचीत का कार्यक्रम है।

ताइवान के डिफेंस जोन में फिर घुसे चार चीनी सैन्य

- अप्रैल माह में सातवी बार चीनी विमानों को एडीआईजेड के दक्षिण-पश्चिम सेक्टर में देखा गया

ताइपे (ईएमएस)। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर चीन के चार सैन्य विमानों ने ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (एडीआईजेड) में प्रवेश किया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार शेनयांग जे-11 लड़ाकू जेट, शानक्सी वाई-8 ईडब्ल्यू इलेक्ट्रानिक युद्धक विमान, सीएआईसी डब्ल्यूजेड-10 हेलीकाप्टर और रूसी निर्मित एमआई-17 कार्गो हेलीकाप्टर शामिल थे। दरअसल, विमान ताइवान के एडीआईजेड के दक्षिण-पश्चिम सेक्टर में दिखाई दिए। जिसके बाद ताइवान की ओर से चीनी विमानों को क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी दी गई। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने विमान की गतिविधियों की निगरानी के लिए वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली तैनात की है। अप्रैल माह में ये सातवी बार है कि जब जब चीनी विमानों को एडीआईजेड के दक्षिण-पश्चिम सेक्टर में देखा गया है। घुसपैठ को व्यापक रूप से चीन द्वारा ताइवान की वायु रक्षा बलों को कम करने के प्रयासों के रूप में वर्णित किया गया है।

ताइवान के अनुसार एडीआईजेड एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी देश के हवाई क्षेत्र से आगे तक फैला हुआ है। जहां हवाई यातायात नियंत्रक आने वाले विमानों से खुद की पहचान करने के लिए कहा जाता है। गौरतलब है ?कि बीजिंग ताइवान पर पूर्ण संप्रभुता का दावा करता है। जबकि दोनों पक्ष सात दशकों से अधिक समय से अलग-अलग शासित हैं, इस तथ्य के बावजूद भी वह यह दावा करता है। यह देश चीन के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित है जिसमें लगभग दो करोड़ 40 लाख लोगों रहते हैं। दूसरी ओर, ताइपे ने अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ाकर चीनी आक्रामकता का मुकाबला किया है, जिसका बीजिंग द्वारा बार-बार विरोध किया गया है। चीन ने धमकी दी है कि ताइवान की आजादी का मतलब युद्ध है।

वित्त वर्ष 2021-22 में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़क?र 4,29,217 इकाई पहुंची

- दोपहिया खंड में हीरो इलेक्ट्रिक 65,303 इकाइयों की बिक्री के साथ प्रथम स्थान पर रही

नई दिल्ली (ईएमएस)। वाहन वित्त वर्ष 2021-22 में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल खुदरा बिक्री तीन गुना से अधिक होकर 4,29,217 इकाई पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में फाडा के अनुसार, 2019-20 में देश में 1,68,300 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए थे। बीते वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री तीन गुना के उछाल के साथ 17,802 इकाई रही, जो 2020-21 में 4,984 इकाई थी। इस खंड में घरेलू वाहन कंपनी टाटा मोटर्स 15,198 इकाइयों की खुदरा बिक्री साथ सबसे आगे रही। उसकी बाजार हिस्सेदारी 85.37 प्रतिशत रही। मुंबई की कंपनी की खुदरा बिक्री 2020-21 में 3,523 इकाई रही थी। एमजी मोटर इंडिया 2,045 इकाइयों की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही। उसकी बाजार हिस्सेदारी 11.49 प्रतिशत पर थी। 2020-21 में एमजी मोटर की बिक्री 1,115 इकाई रही थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा 156 इकाइयों की बिक्री के साथ तीसरे और हुंदै मोटर 128 इकाइयों की बिक्री के साथ चौथे स्थान पर रही। दोनों की बाजार हिस्सेदारी एक फीसदी से कम थी। बीते वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री पांच गुना बढ़कर 2,31,338 इकाई पर पहुंच गई जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 41,046 इकाई थी। दोपहिया खंड में हीरो इलेक्ट्रिक 65,303 इकाइयों की बिक्री के साथ शीर्ष पर रही। उसकी बाजार हिस्सेदारी 28.23 प्रतिशत थी।

इसके बाद ओकिनावा ऑटोटेक दूसरे स्थान पर रही। उसकी बिक्री 46,447 इकाइयों की रही। तीसरे स्थान पर 24,648 इकाइयों की बिक्री के साथ एम्पियर वेहिकल्स रही। हीरो मोटोकॉर्प समर्थित अथर एनर्जी ने बीते वित्त वर्ष में 19,971 इलेक्ट्रिक दोपहिया बेचे और वह चौथे स्थान पर रही। बेंगलुरु की कंपनी ओला इलेक्ट्रिक 14,371 वाहनों की बिक्री के साथ छठे और टीवीएस मोटर कंपनी 9,458 वाहनों की बिक्री के साथ सातवें स्थान पर रही। फाडा ने 1,605 में से 1,397 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) से आंकड़े जुटाए हैं। फाडा ने कहा कि बीते वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक तिपहिया की बिक्री बढ़कर 1,77,874 इकाई पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 88,391 इकाई थी। इसी तरह इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 400 इकाइयों से बढ़कर 2,203 इकाई पर पहुंच गई।

हिजाब पर अलकायदा के हसितक्षेप पर भारत के मुस्लिम संगठन बोले- हमारा आंतरिक मामला नसीहत की जरूरत नहीं

नई दिल्ली (ईएमएस)। कर्नाटक में हिजाब विवाद के तूल पकड़ने के बाद मामला दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। घटना दौरान 'जय श्रीराम' के नारों के जवाब में 'अल्लाहू अकबर' का नारा बुलंद करने वाली मुस्कान जैनब खान के समर्थन में अलकायदा प्रमुख जवाहिरी का वीडियो सामने आने के बाद देश के मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अलकायदा को कड़े शब्दों में कहा है कि, यह भारत का आंतरिक मामला है, हमें नसीहत की जरूरत नहीं। कर्नाटक के मांडया की रहने वाली कॉलेज छात्रा मुस्कान जैनब खान हिजाब विवाद के दौरान एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरी हैं।

दुनिया के बड़े आतंकी संगठनों में शुमार अलकायदा के प्रमुख जवाहिरी द्वारा मुस्कान की तारीफ पर अखिल भारतीय इमाम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा कि, हम अलकायदा की बातों से मतलब नहीं रखते हैं, यह हमारे अंदरूनी मामले हैं। हम इन्हें आपस में समेट लेंगे। यह बाहरी शक्तियां हैं जो मुल्क के अंदर नफरत फैलाना चाहती हैं। मुल्क में झगड़े कराना चाहती हैं, इसलिए हमें अलकायदा की नसीहतों की जरूरत नहीं हैं। यह हमारा मुल्क है और यह बाहर से आकर हमारे लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं, यह हमारे लिए हमदर्दी नहीं बल्कि यह मुस्लिम समाज के लिए नुकसान देह है। यह संगठन इंसानियत के दुश्मन हैं और मुल्क को तोड़ने की साजिशें रच रहे हैं।उन्होंने आगे कहा कि, तमाम मुस्लिम समाज से अपील करना चाहता हूं कि, यह संगठन अपने बिलों से निकलकर तारीफ कर रहे हैं। यह नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे बाहरी संगठनों के उकसाने में नहीं आना है, मुल्क के साथ खड़े होकर साथ रहना है।

अयमान अल जवाहिरी आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन का करीबी माना जाता रहा है। 2011 में अमेरिकी हमले में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद जवाहिरी ने अल कायदा की बागडोर संभाली थी। इससे पहले अलकायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी के बारे में साल 2020 में ये खबर फैली कि उनकी मौत हो चुकी है या फिर वो बीमार हो चुके हैं। वहीं बीते दिनों अलकायदा प्रमुख जवाहिरी ने मुस्कान की तारीफ में करीब नौ मिनट का वीडियो संदेश जारी किया, वीडियो पर कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि मुस्लिम सगठनों की अलकायदा की टिपण्णी से पहले ही मुस्कान के पिता मोहम्मद हुसैन खान ने ही वीडियो से किनारा कर लिया था, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि, उनका अलकायदा से कोई लेना देना नहीं है। जवाहिरी कौन यह भी वह नहीं जानते। हमें उनकी तारीफ की जरूरत नहीं है। हम यहां खुश हैं।

पाक की कमान संभालने से पहले ही शहबाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर दिया सकारात्मक बयान

इस्लामाबाद (ईएमएस)। पाकिस्तान में इमरान खान के क्लीन बोल्ड होने के बाद हालात बदल चुके है। महीने भर से चले सियासी ड्रामे के बाद इमरान खान को सत्ताबदर होना ही पड़ा। पाकिस्तान में मचे इस सियासी उथल पुथल का असर न केवल उनके मुल्क में बल्कि भारत समेत पड़ोस के कई देशों में भी असर पड़ेगा। नई सरकार के बनने के बाद भारत के साथ उसके संबंधों पर किस तरह का रूख रखा जाएगा। इन सारी बातों के बीच विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है।

उन्होंने कहा है कि वे भारत के साथ शांति चाहते हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि कश्मीर के मुद्दे के समाधान के बिना शांति संभव नहीं है। पीएम उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं होने तक भारत के साथ संबंध सामान्य नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि हम भारते के साथ शांति चाहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ चल रहे मामलों को लेकर शहबाज ने कहा कि उनमें कानून के अनुसार कार्यवाही जारी रहेगी। संयुक्त विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने रहा है कि पाकिस्तान की नई सरकार आगे बढ़ना चाहती है और बदले की राजनीति नहीं करना चाहती है।

मालूम हो कि इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने रविवार को खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया, जबकि पूर्व सत्तारूढ़ दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने पद के लिए शाह महमूद कुरैशी को अपना उम्मीदवार नामित किया। पाकिस्तान में विपक्षी दल के शीर्ष नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद उन पर कटाक्ष करते हुए रविवार को कहा, 'हम (आपका) पुराने पाकिस्तान में फिर से स्वागत करते हैं।' 'नया पाकिस्तान' बनाने के वादे के साथ 2018 में सत्ता में आए खान को प्रधानमंत्

हिम्मतनगर और आणंद में रामनवमी पर शोभायात्रा के दौरान पथराव से तनाव

अहमदाबाद । उत्तर गुजरात के हिम्मतनगर और आणंद में रविवार को रामनवमी पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान पथराव हुआ। इसके बाद इलाके में तनाव उत्पन्न हो गया। पुलिस ने पांच राउंड टीयर गैस छोड़ी तथा उपद्रवियों को तितर- बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने घटना पर चिंता जताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। रामनवमी पर्व पर रविवार को हिम्मतनगर में शोभायात्रा का आयोजन किया गया। छापरिया इलाके में स्थित राममंदिर व हनुमान मंदिर के पास शोभायात्रा में पथराव हुआ। पथराव के आरोपितों का हाल कोई पता नहीं चल सका है। पथराव के बाद गुस्साए लोगों ने आसपास के वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने टीयर गैस व हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवियों पर काबू पा लिया है। गृह राज्यमंत्री संघवी ने सूचना मिलने के बाद घटना पर निगरानी रखी तथा पुलिस अधिकारियों को दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

आणंद जिले के खंभात कस्बे में रामनवमी जुलूस के दौरान संघर्ष शुरू हो गया। दो समूहों के पथराव में दुकान व वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। यहां भी स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। गुजरात के हिम्मतनगर और आणंद में रामनवमी पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान पथराव हुआ। इसके बाद इलाके में तनाव उत्पन्न हो गया। पुलिस ने पांच राउंड टीयर गैस छोड़ी तथा उपद्रवियों को तितर- बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया।

गत दिनों आणंद जिले के पेटलाद में एक धार्मिक जुलूस में तेज संगीत बजाने को लेकर दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान पथराव में पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि पेटलाद कस्बे के बोरिया गांव में मंगलवार को तेज संगीत पर माताजी का जुलूस निकालने के दौरान एक समुदाय के लोगों की दूसरे समुदाय के लोगों से कहासुनी हुई। इसके बाद एक-दूसरे पर पथराव करने लगे। दर्ज शिकायत के अनुसार, पुलिस मौके पर पहुंची और तनाव को कम करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने एक-दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे पांच लोग घायल हो गए। दोनों समुदायों के करीब एक सौ लोगों के खिलाफ धारा 143 (गैरकानूनी सभा), 147 (दंगा), 337 (जल्दी और लापरवाही से जीवन को खतरे में डालना), और 504 (सार्वजनिक शांति को भड़काने और तोड़ने के लिए अपमान) और अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। उन्होंने कहा कि गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थिति शांतिपूर्ण है। गत दिनों राजस्थान के करौली में इसी तरह एक धार्मिक जूलूस पर हमला कर दिया गया था, इसके बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा में भारी हिंसा व आगजनी हुई थी।

गुजरात के हिम्मतनगर और आणंद में रामनवमी पर निकाली गई शोभायात्रा के दौरान पथराव हुआ। इसके बाद इलाके में तनाव उत्पन्न हो गया। पुलिस ने पांच राउंड टीयर गैस छोड़ी तथा उपद्रवियों को तितर- बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया।

राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश ने की भगवान द्वारकाधीश की पूजा-अर्चना

अहमदाबाद । राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने रामनवमी पर रविवार को गुजरात के द्वारका मंदिर में परिवार के साथ भगवान द्वारकाधीश के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। राष्ट्रपति ने देश की सुरक्षा, समृद्धि के साथ जनता के सुखी होने प्रार्थना की की। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने भी द्वारका मंदिर में दर्शन किए तथा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर पूजा-अर्चना की। राष्ट्रपति विशेष विमान से जामनगर वायुसेना के हेलीपेड पहुंचे। यहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनकी अगवानी की। यहां से राष्ट्रपति पत्नी सविता व पुत्री स्वाति के साथ सीधे द्वारका मंदिर में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने पहुंचे। यहां द्वारका मंदिर ट्रस्ट की ओर से कलक्टर एमए पंडया, धनराज नथवाणी आदि ने उनका स्वागत किया। नथवाणी ने राष्ट्रपति को भगवान द्वारकाधीश की पेंटिंग भेंट की।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थानीय निदेशक नंदिनी भट्टाचार्य ने राष्ट्रपति को जगत मंदिर के स्थापत्य तथा इसके इतिहास की जानकारी दी। राष्ट्रपति ने मंदिर में पूजा-अर्चना की तथा देश की सुरक्षा, समृद्धि के साथ जनता के सुखी होने की भगवान से प्रार्थना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भी सपत्नी रविवार को द्वारका मंदिर पहुंचे, भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के बाद इस दंपती ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचकर विशेष पूजा की। राष्ट्रपति ने ट्वीट में लिखा कि सभी देशवासियों को राम नवमी की शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जीवन, उनकी कर्तव्यनिष्ठा और उच्च आदर्श पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा के स्रोत हैं। आइए, हम सब प्रभु राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान का संकल्प लें।

मध्यस्थता समेत विवाद के वैकल्पिक समाधान (एडीआर) तंत्र से भारतीय कानूनी व्यवस्था की सूरत बदल सकती है, लेकिन कुछ अड़चनों के चलते इसे अभी व्यापक स्वीकार्यता नहीं मिली है। गुजरात के केवडिया में आयोजित एक सम्मेलन में राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द समेत विभिन्न वक्ताओं ने ये विचार व्यक्त किए। 'स्टैच्यू आफ यूनिटी' के पास टेंट सिटी में 'मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी' पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति कोविन्द ने कहा, 'सच कहा जाए, तो मध्यस्थता में हर कोई विजेता होता है। ऐसा कहते हुए हमें यह भी मानना होगा कि देशभर में अभी इस अवधारणा को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। कुछ जगहों पर तो पर्याप्त प्रशिक्षित मध्यस्थ भी नहीं हैं। कई मध्यस्थता केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने की सख्त जरूरत है।' सर्वसुलभ न्याय के लिए संचार माध्यमों में सुधार की जरूरत राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों की न्याय तक पहुंच व इसे सर्वसुलभ बनाने को सूचना एवं संचार माध्यमों में सुधार की जरूरत है। मध्यस्थता के रास्ते की अड़चनों को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रभावी उपाय का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर वांछित परिणाम हासिल करना है तो सभी हितधारकों को मध्यस्थता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करना होगा। उन्होंने इसे अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए प्रशिक्षण पर भी जोर दिया।

जातिगत जनगणना से क्यों भाग रही है भाजपा सरकार : कांग्रेस

अहमदाबाद (ईएमएस) कांग्रेस ने भाजपा सरकार के जातिगत जनगणना से भागने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वह निजीकरण की आड़ में आरक्षण खत्म करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री कैप्टन अजयसिंह यादव ने कहा कि ओबीसी समेत वर्गों को मिलने योग्य सहायता, योजना के बजट में कटौती कर उनके साथ केन्द्र की भाजपा सरकार अन्याय कर रही है देश के 85 प्रतिशत ओबीसी समेत सामान्य मध्यम वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना पर केवल 25 प्रतिशत बजट खर्च करने की घोषणा की जाती है उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर भाजपा सरकार जातिगत जनगणना कराने से क्यों भाग रही है? कांग्रेस शासन के दौरान वर्ष 1991 में मंडल कमीशन लागू किया गया था, जिससे देश के ओबीसी समाज समेत अन्य वर्ग के लोगों को फायदा हुआ थ संविधान में दिए गए आरक्षण को निजीकरण की आड में खत्म किया जा रहा है वर्ग 3-4 के कर्मचारियों के संतानों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पंचायती राज से ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया है सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण कर भाजपा सरकार आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है एलआईसी, रेलवे, ओएनजीसी, राष्ट्रीय बैंक समेत मुनाफा कमाने वाली कंपनियों और संस्थाओं का निजीकरण कर भाजपा व आरएसएस आरक्षण प्रथा को ही खत्म करने की साजिश रच रहे हैं निजीकरण के जरिए भाजपा सरकार अपने करीबियों को फायदा पहुंचा रही है गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जगदीश ठाकोर ने पार्टी के ओबीसी विभाग के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई और रोजगार के बजाए भाजपा केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर मूलभूत मुद्दों से लोगों को ध्यान भटका रही है पिछड़े-शोषित वर्ग को योग्य शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रहीं और इसके लिए बनाए गए निगम को पर्याप्त फंड नहीं दिया जा रह जिसकी वजह से योजनाओं को उचित अमलीकरण के अभाव में दूरदराज के नागरिकों को लाभ नहीं मिलत करोड़ों रुपए उत्सवों-नौटंकियों, विमान खरीदी पर खर्च किए जाते हैं, जबकि यह रुपए गरीब, सामान्य नागरिकों की बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किए जाने चाहिए जगदीश ठाकोर ने कहा कि संविधान में दिए गए आरक्षण का सरकार योग्य अमल करे और सरकारी संस्थाओं का विकास के नाम पर निजीकरण बंद करें कांग्रेस देश में ओबीसी समेत वर्गों के लिए जनसंख्या के हिसाब से बजट आवंटित करने की भाजपा सरकारक से मांग करती है गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष घनश्याम गढवी ने कहा कि गुजरात में ओबीसी, एससी, एसटी विरोधी भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ ओबीसी डिपार्टमेंट चार मंडल में सम्मेलन करेगा गुजरात में ओबीसी की आबादी के हिसाब से बजट में आवंट करने, गुजरात विधानसभा में पास पशु नियंत्रण कानून रद्द करने, गुजरात के ग्रामीण इलाकों में 5612 प्राथमिक स्कूलें बंद करने के फैसले तत्काल रद्द करने और प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार मिले इसके लिए तुरंत कानून लागू करने, गुजरात राज्य के समाज के लिए बोर्ड-निगम का गठन करने का कांग्रेस मांग करती है

प्रत्येक जिले में ७५ अमृत सरोवर बनाएं : नरेन्द्र मोदी

पाटीदार पाणीदार तब ही बनेगा जबकि पाणी हो : प्रधानमंत्री

जूनागढ़ के गांठिला मंदिर में रविवार को महापाटोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ, उमाधाम के महापाटोत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्च्युअली शामिल हुए

जूनागढ़, १० अप्रैल ।

जूनागढ़ के गांठिला मंदिर में रविवार को महापाटोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है । उमाधाम के महापाटोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वर्च्युअली शामिल हुए । अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पाणी, प्राकृतिक खेती, प्लास्टिक मुक्त जीवन और कुपोषण पर भार दिया । उन्होंने समाज में यह बातों की कितनी जरूरत है यह मामले में बताया । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पाटीदार समाज को अपील करते हुए कहा कि गांव गांव में उमियाधाम ट्रस्ट द्वारा तंदुरस्त बच्चा स्पर्धा करे, कुपोषण मुक्त गुजरात बनाने के लिए आह्वान किया, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गांव गांव में तालाब गहरा बनाकर अमृत तालाब बनाओ, प्रत्येक जिले में ७५ तालाब बनाने के लिए आह्वान, नेताओं के द्वारा झंडे की सलामी नहीं लेकिन गांव के बुजुर्ग लोगों द्वारा यह जगह पर झंडे की सलामी होनी चाहिए और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की अपील की थी । संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि, दूर से पुराने जोगी के दर्शन हो रहे है यह खुशी का समय है । आज चैत्री नवरात्रि का नौवां दिन है । सभी को मंगल कामना है कि मां सिद्धदात्री आपकी इच्छा पूरी करें । मैं सामूहिकता की शक्ति का हमेशा महसूस किया है । आज श्रीराम का प्रोग्त्यमहोत्सव है । मुझे पहले भी यहां आने का मौका मिला है । यह पावनधाम श्रद्धा का केंद्र तो है, लेकिन अब यह स्थान सामाजिक चेतना का केंद्र तथा टूरिजम क्षेत्र हुआ है । मां उमिया के भक्त जो भी पूरा करने का हो वह पूरा करने का प्रयास आप लोगों ने किया है । इसके लिए कर्ताधर्ताओं को कई अभिनंदन है । मुख्यमंत्री ने भावनात्मक बात की । उन्होंने कहा धरती माता है । मैं उमिया माता का भक्त होऊ तो धरती माता को पीड़ा देने का कोई कारण नहीं है । धरती माता को बचाने का बड़ा अभियान है । भूतकाल में हमने पानी की कमी में जी रहे लोग । सूखे की हमेशा चिंता रही है । लेकिन पाणी के लिए कई अभियान चलाये गये । पानी के लिए कोशिश की ।

समूचे देश में 'नडाबेट सीमा दर्शन परियोजना' के कारण बनासकांठा आकर्षण का केंद्र बनेगा : अमित शाह

बनासकांठा, १० अप्रैल ।

राज्य के सीमा जिला बनासकांठा के नडाबेट में सीमादर्शन प्रॉजेक्ट का प्रारंभ गृहमंत्री अमित शाह ने कराया है । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीमादर्शन प्रॉजेक्ट का उद्घाटन कराया है । यह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और कई उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे । गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने माता नडेश्वरी के दर्शन भी किए । सीमादर्शन प्रॉजेक्ट शुरू करने का उद्देश्य देश की सीमा को सुरक्षित रखते वीर जवानों की रहणी-करणी, ड्यूटी और देशप्रेम को निकट से लोग दे सके इसका है । राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाला वीर सैनिकों की स्मृति में अजय प्रहरी स्मारक का निर्माण किया गया है तथा ४० फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया गया है । इसके अलावा, पर्यटक भारत-पाकिस्तान बॉर्डर का नजारा देखने का रोमांचक अनुभव भी कर सके इसके लिए बीएसएफ द्वारा बीटिंग रिट्रीट समारोह का भी आरंभ कराया गया है । जवानों के शौर्य से भरपूर दृश्यों को देखकर पर्यटकों के दिल में जवानों के प्रति अनोखा गर्व और श्रद्धा की भावना पैदा होगी । रविवार को अमित शाह ने ४० फीट ऊंचे से तिरंगा लहराकर सीमा दर्शन प्रॉजेक्ट को खुला रखा गया । उन्होंने नडेश्वर माताजी का आर्शीवाद भी लिया था । पर्यटकों को नडाबेट में भारतीय सेना और बीएसएफ के हथियारों जैसे कि, जमीन से जमीन पर और जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल्स, टी-५५ टैंक, आर्टिलरी गन, टोरपीडो, विंग ड्रोप टैंक तथा मिग-२७ एयरक्राफ्ट को देख सके ऐसी व्यवस्था का भी प्रारंभ किया गया है । नडाबेट सीमादर्शन प्रॉजेक्ट देश में बीएसएफ का प्रथम आधुनिक प्रॉजेक्ट है, जो बीएसएफ के उद्भव, विकास और युद्धों में इसकी भूमिका तथा सिद्धि सहित देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों की गौरवगाथा का सचित्र दर्शन करायेगा ।

माधवपुर मेला भारत की सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता का अनूठा उत्सवः पीएम मोदी

अहमदाबाद (ईएमएस) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम से एक क्लिप साझा की है, जिसमें उन्होंने माधवपुर मेले को भारत की सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता के अनूठे उत्सव के रूप में विस्तार से बताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा- ठमाधवपुर मेले की शुरुआत के साथ, भारत की सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता के इस अनूठे उत्सव के बारे में पिछले महीने क्ष्मनकीबात के दौरान मैंने जो कहा था, उसे साझा कर रहा हूँ।ठ प्रधानमंत्री ने मेले की थीम और आनंदपूर्णभावना के बारे में गुजरात पर्यटन के एक ट्वीट को भी साझा किया।

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादकः लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोनः 079-22921482 Mob.9375504122, 9327086467 R.N.I. 63177/95